शर्मा शर्डওয়েৰ
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in

हिंदी दैनिक

गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

विकसित भारत समाचार

वर्ष : 13 | अंक : 93 | गुवाहाटी | गुरुवार, 5 नवंबर, 2026 | मूल्य : 2 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेट्स की ऐतिहासिक जीत पेज 2

असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने ग्वालपाड़ा में पदयात्रा में लिया हिस्सा पेज 3

राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने की इतनी इच्छा है तो बांग्लादेश जाकर... पेज 5

एशियन पैरा गेम्स में उपलब्धियों की बरसात : 1538 पदक जीते गए... पेज 7

गुवाहाटी होटल विलास इन हत्याकांड

पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी ढेर

जवान की पिस्तौल छीनी, एसआई घायल



गुवाहाटी। गुवाहाटी के *होटल बिलास इन* में 26 अक्तूबर को हुई गोलीबारी की घटना में पांच लोगों की मौत हो गई थी। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी घनकांत गोगोई बुधवार तड़के पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। असम के शिवसागर जिले में यह मुठभेड़ बुधवार सुबह करीब 3:10 बजे गौरीसागर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत रोंगमन ढाबा के पास फूलपानी सिगार में हुई। शिवसागर पुलिस की एक टीम रात को एक लंबित मामले के सिलसिले में मुख्य आरोपी घनकांत गोगोई को गुवाहाटी से वापस ला रही थी। पुलिस के मुताबिक, *-शेष पृष्ठ दो पर*

मुख्यमंत्री ने राहुल को सड़क पर नहीं पार्लियामेंट में बहस की दी चुनौती



गुवाहाटी (हि.स.)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पब्लिक डिबेट की चुनौती देने पर तीखा पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर आज एक वीडियो पोस्ट करते हुए राहुल गांधी पर पलटवार किया है। गांधी के ओपन डिबेट के प्रस्ताव पर जवाब देते हुए, डॉ. शर्मा ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस नेता विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं और पूछा कि वे चर्चा कहां करना चाहते हैं — सड़क पर, किसी गली में या पार्लियामेंट में। डॉ. शर्मा ने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का जिक्र करते हुए कहा कि जब पार्लियामेंट में स्पीकर हैं तो आपको जज के तौर पर डॉ. मोहन भागवत *-शेष पृष्ठ दो पर*

राज्य में 17 में से 12 विशेष कैंसर अस्पताल चालू, पांच और अस्पताल निर्माणाधीन : सीएम



गुवाहाटी (हि.स.)। असम सरकार राज्य में कैंसर मरीजों को उनके घर के नजदीक उन्नत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष कैंसर अस्पतालों के नेटवर्क का विस्तार कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि राज्य में प्रस्तावित 17 विशेष कैंसर अस्पतालों में से 12 पहले ही काम करना शुरू कर चुके हैं, जबकि पांच अन्य अस्पतालों की स्थापना की *-शेष पृष्ठ दो पर*





CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
94350-14771

खाई में गिरा सेना का वाहन, दो जवान शहीद

लेह। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग-01 पर नामिका ला दर्रे के पास बुधवार, 4 नवंबर को सेना का एक भारी वाहन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरा। इस दर्दनाक हादसे में वाहन चालक और सह-चालक सहित भारतीय सेना के दो जवान बलिदान हो गए। घटना की सूचना मिलते ही जिला पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चलाया। गहरी खाई से कड़ी मशक्कत के बाद दोनों जवानों के शवों को बाहर निकाला गया। इसके बाद सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए शवों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), चिकतान पहुंचाया गया।

अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेट्स की ऐतिहासिक जीत

राष्ट्रपति ट्रंप ने नतीजों को स्वीकार किया

वाशिंगटन (हि.स.)। अमेरिकी मतदाताओं ने मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका दिया है। मतगणना के नतीजे चौंकाने वाले हैं। सीएनएन और सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार डेमोक्रेट्स ने अमेरिका संसद (कांग्रेस) पर फिर नियंत्रण हासिल कर लिया है। कांग्रेस के निचले सदन यानी प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) की 425 सीटों के लिए लिए हुए चुनाव में डेमोक्रेट्स ने 224 सीटों पर जीत हासिल की है। रिपब्लिकन को 129 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। अब तक के नतीजों में डेमोक्रेट्स ने बहुमत का आंकड़ा 218 पार कर लिया है। बाकी अधिकांश सीटों पर भी डेमोक्रेट्स उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। सीएनएन और सीबीएस न्यूज चैनल की चुनाव डेस्क से प्रसारित समाचारों में बताया गया है कि इसके अलावा 100 सदस्यीय सीनेट (उच्च सदन) की 35 सीट और 36 गवर्नर के पदों के नतीजे भी आने लगे हैं। इनमें से 33 सीटों पर नियमित रूप से 6 साल के



कार्यकाल के लिए मतदान हुआ है। बाकी की दो सीटें (ओहायो और फ्लोरिडा) विशेष चुनाव के तहत हैं। ये सीटें जेडी वेंस के उपराष्ट्रपति बनने के कारण और मार्को रुबियो के विदेश मंत्री बनने के कारण के दिए गए इस्तीफे से खाली हुई थीं। सीनेट की शेष 65 सीटों पर इस बार चुनाव नहीं हुआ है, क्योंकि अमेरिकी सीनेट के केवल एक-तिहाई सदस्यों के लिए ही हर दो साल में चुनाव कराए जाते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी ने रिपब्लिकन गढ़ माने जाने वाले कई राज्यों में जीत दर्ज कर सात सीटों का फायदा हासिल किया। सदन में उनकी संख्या बढ़कर 53 हो गई है। रिपब्लिकन पार्टी की सीट घटकर 42 हो गई है। दोनों समाचार चैनलों की रिपोर्ट के अनुसार, डेमोक्रेट्स ने उन जगहों पर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है, जहां दो साल पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने आसानी से जीत हासिल की थी। डेमोक्रेट्स ने हाउस और सीनेट दोनों पर शानदार और ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इससे उन्हें ट्रंप के कार्यकाल के आखिरी दो सालों में उन पर लगाम लगाने के लिए काफी ताकत मिल गई है। ट्रंप ने *द न्यूयॉर्क टाइम्स* से कहा कि वह नतीजों को स्वीकार करते हैं। इससे फिलहाल उन सवालों पर विराम लग गया है कि क्या वे नतीजों को चुनौती देंगे। फॉक्स न्यूज के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे रिपब्लिकन पार्टी की पराजय को *अपने ऊपर लगे झटके* के तौर पर नहीं देखते हैं।

नेतन्याहू का संसदीय बहुमत समाप्त, सत्ता की चाबी अब अरब पार्टियों के हाथ



यरुशलेम। इजराइली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने बुधवार को पिछले हफ्ते हुए मतदान के प्रमाणित नतीजों को स्वीकार कर लिया और कहा कि वह नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी और उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी, पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोट की पार्टी दोनों में से किसी को भी संसद में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। अब दोनों पक्ष छोटी पार्टियों को अपने साथ मिलाकर नई सरकार बनाने के लिए कड़ी बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले, इजराइल के चुनाव आयोग ने कहा कि उसे पिछले हफ्ते हुए मतदान में कोई धांधली नहीं मिली है। इससे नतीजों को गलत साबित करने की नेतन्याहू की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। नेतन्याहू और उनके समर्थकों ने बार-बार बिना किसी सबूत के यह दावा किया है कि अरब-नेतृत्व वाली पार्टियों ने चुनाव *चुरा* लिया है, और हो सकता है कि इसमें उन्हें विदेशी मदद भी मिली हो। परिणामों से पता चला कि नेतन्याहू के धार्मिक-राष्ट्रवादी गुट ने संसद में अपना बहुमत खो दिया है, जबकि अरब-नेतृत्व वाले दलों को काफी फायदा हुआ है। आयोग ने एक बयान में कहा कि समीक्षा में ऐसी किसी भी अनियमितता का कोई सबूत नहीं मिला, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर आंच आई हो या नतीजों पर कोई असर पड़ा हो। चुनाव समिति के कार्यवाहक निदेशक, डीन लिवने ने कहा कि उनकी जांच में हर शिकायत की *अलग-अलग और बारीकी से* पड़ताल की गई, लेकिन चुनाव परिणामों के अमान्य होने के आरोपों का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं मिला। लिवने ने आगे कहा कि ये नतीजे, जिन्हें बुधवार को औपचारिक रूप से प्रमाणित किया जाना है कि मतदाताओं द्वारा मतदान के दौरान किए गए विकल्पों को सही ढंग से दर्शाते हैं। चुनाव समिति के एक प्रवक्ता के अनुसार, चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों को लेकर शिन बेट खुफिया सेवा द्वारा एक अलग जांच की जा रही है। चुनाव समिति ने कहा है कि हालांकि ये आरोप गंभीर हैं कि विदेशी ताकतों ने चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन उनका मानना है कि इस तरह के किसी भी हस्तक्षेप का चुनाव के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ा। समिति के प्रमुख, उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति नोम सोहलबर्ग ने रविवार को कहा कि हमारा मानना है कि अगर ये संदेह सही भी साबित होते हैं, तो भी इससे चुनाव प्रक्रिया या कुल मिलाकर चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता पर कोई आंच नहीं आएगी। नेतन्याहू के अभियान दल ने टिप्पणी के अनुरोध पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रमाणित चुनाव परिणाम मिलने के बाद इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग अब संसद के लिए चुनी गई सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात शुरू करेंगे।

अग्निवीरों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला

75 प्रतिशत की आर्मी में होगी भर्ती, दो साल का सेवा विस्तार

नई दिल्ली। अग्निपथ ढांचे में किए गए बदलावों के तहत, जिन अग्निवीरों का चयन नियमित भर्ती के लिए नहीं हो पाता है, उन्हें दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल दिया जाएगा। इससे उनकी कुल सेवा अवधि चार साल से बढ़कर छह साल हो जाएगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान इस फैसले की घोषणा की। मौजूदा नियमों के अनुसार, मेरिट के आधार पर 25 प्रतिशत तक अग्निवीरों को नियमित सेना में शामिल किया जा सकता है। बाकी बचे 75 प्रतिशत अग्निवीरों को, अपनी शुरुआती चार साल की सेवा पूरी करने के बाद, दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल दिया जाएगा। इस विस्तारित कार्यकाल के अंत में, जो अग्निवीर आगे भी सेवा जारी रखना चाहेंगे, उन्हें सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए विचार किया जाएगा, जिसके लिए कुछ तय चयन मानदंड लागू होंगे। सीडीएस ने कहा कि योग्यता के आधार पर 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सेना में शामिल किया जाएगा। पहले, 75 प्रतिशत अग्निवीरों के लिए यह प्रावधान था कि वे अनुशासित और प्रेरित युवाओं के रूप में वापस समाज में लौट जाएं। हालांकि, इस अद्यतन (अपडेटेड) योजना के तहत, बाकी 75 प्रतिशत अग्निवीरों को अब दो साल की अतिरिक्त सेवा अवधि का मौका दिया जाएगा। यह दो साल की अवधि पूरी होने पर, जो भी इच्छुक होंगे, उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल कर लिया जाएगा; इसके लिए चयन के कुछ निश्चित मानदंड होंगे। इस योजना के ये चार मुख्य पहलू हैं। इस बीच, अग्निवीरों का पहला बैच 21 नवंबर को सेवा से बाहर हो जाएगा। भारतीय नौसेना के पहले बैच में लगभग 2,100 अग्निवीरों को शामिल किया गया था, जिनमें से करीब 550 (लगभग 25 प्रतिशत) को रिटेंशन पॉलिसी के तहत नौसेना में स्थायी रूप से रख लिया गया है। बाकी बचे अग्निवीरों को पहले अपने चार साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवा से बाहर होना था। हालांकि, अब अद्यतन ढांचे (अपडेटेड फ्रेमवर्क) के तहत, उन्हें दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल देने का प्रस्ताव दिया जाएगा। भारतीय नौसेना के साथ-साथ, भारतीय वायु सेना और थल सेना में

प्रधानमंत्री बहस कर लें, पांच मिनट में साबित कर दूंगा कि वह *देशद्रोही* हैं : राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर खुली बहस की चुनौती देते हुए कहा कि यदि मोदी उनके साथ बहस करते हैं तो वह पांच मिनट में साबित कर देंगे कि प्रधानमंत्री *देशद्रोही* हैं और वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर काम करते हैं। गांधी ने पंजाब के संगरूर में कांग्रेस की *इंसाफ रैली* को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री चाहे हैं तो बहस के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत या फिर उद्योगपति गौतम अदाणी को जज बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस नेताओं को देशद्रोही कहते हैं। मैंने उन्हें सीधी चुनौती दी कि आप मेरे साथ बहस करिए। जिसको आप जज बनाना चाहते हैं, बना दीजिए। मोहन भागवत को जज बना दीजिए, अदाणी जी को बनाना है तो उन्हें जज बना दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस मेरे सामने आकर बैठ जाइए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का कहना था कि मैं देश को गारंटी देता हूं कि नरेंद्र मोदी मेरे सामने आकर बैठ नहीं सकते। उनके सारे नेता कह रहे हैं कि संसद में चर्चा करिए, लेकिन संसद में आप लोग मेरा माइक बंद कर देते हैं और मुझे बोलने नहीं देते हैं। उन्होंने दावा किया कि आप (भाजपा नेता) नरेंद्र मोदी को मेरे सामने बैठने के लिए कहिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि पांच मिनट में साबित कर दूंगा कि नरेंद्र मोदी देशद्रोही हैं और मोदी को डोनाल्ड ट्रंप नियंत्रित करते हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के साथ पांच मिनट में व्यापार समझौता कर लिया और ट्रंप की ओर से धमकी दिए जाने पर भारत के किसानों, छोटे व्यापारियों के हितों और देश का डेटा तक उनके हवाले कर दिया। गांधी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार-बार दावा करते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस पर कुछ नहीं बोलते। उन्होंने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते और उद्योगपति गौतम अदाणी के खिलाफ अमेरिका में चल रहे मामले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि समझौते के बाद ट्रंप ने अमेरिका में अदाणी के खिलाफ मामला बंद करवा दिया। अदाणी के खिलाफ अमेरिका में चल रहे मामले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि समझौते के बाद ट्रंप ने अमेरिका में अदाणी के खिलाफ मामला बंद करवा दिया। गांधी ने कहा कि इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। मोदी जी, डरिए मत, आ जाइए, बहस करते हैं। मैं दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। उन्होंने सोमवार और मंगलवार को भी प्रधानमंत्री मोदी को सीधी बहस की चुनौती दी थी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता किरेन रीजीजू ने मंगलवार को गांधी पर पलटवार करते हुए *एक्स* पर पोस्ट किया था कि शीर्ष स्तर की बहस परिपक्व लोगों के बीच होती है। दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में विपक्ष पर निशाना साधा था और कहा था कि जब देश बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब देश के भीतर कुछ ताकतें झूठ और अफवाह फैलाकर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही थीं।

नलबाड़ी में सरकारी शिक्षक नहीं कर सकेंगे पत्रकारिता

गुवाहाटी (हि.स.)। असम के नलबाड़ी जिले में अब कोई भी सरकारी शिक्षक पत्रकारिता नहीं कर सकेगा। जिला शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सख्त रुख अपनाते हुए शिकायत मिलने पर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। जिला शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षकों के पत्रकारिता करने से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है। नलबाड़ी जिले के विद्यालयों के निरीक्षक ने आम लोगों से ऐसी किसी भी गतिविधि की जानकारी विभाग को देने की अपील की है। इसके लिए 99573 92702 नंबर जारी किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिकायत मिलने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मणिपुर में फिर भड़की हिंसा विरोधी गुटों के बीच गोलीबारी में तीन उग्रवादी ढेर



इंफाल। मणिपुर के नोने जिले में बुधवार तड़के प्रतिद्वंद्वी उग्रवादी गुटों के बीच भीषण गोलीबारी हुई। अधिकारियों के मुताबिक, इस मुठभेड़ में कम से कम तीन उग्रवादी मारे गए हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी कि नागा-बहुल नोने जिले के खोपुम क्षेत्र स्थित ताओदाइजंग गांव में सुबह करीब 4 बजे अचानक भारी गोलीबारी शुरू हो गई। यह मुठभेड़ अलग-अलग नागा उग्रवादी संगठनों के कैडरों के बीच होने का संदेह है, जिसमें जेलियांग्रॉन्ग यूनाइटेड फ्रंट और उसका विरोधी संगठन शामिल बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ शांत होने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने घटनास्थल से मारे गए तीनों उग्रवादियों के शव बरामद किए। इलाके में भारी तनाव को देखते हुए स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। घटना के तुरंत बाद आगे की हिंसा और खून-खराबे को रोकने के लिए स्थानीय लोग, विशेषकर महिलाएं, खुद मौके पर पहुंचीं। उन्होंने लाउडस्पीकर के जरिए उग्रवादियों से गोलीबारी तुरंत बंद करने और शांति बनाए रखने की भावुक अपील की।

अगरतला नगर निगम चुनाव : त्रिपुरा कांग्रेस ने 49 वार्डों में उतारे प्रत्याशी, सीपीएम पर लगाया यह आरोप

अगरतला। त्रिपुरा कांग्रेस ने बुधवार को 51 वार्ड वाले अगरतला नगर निगम (एएमसी) चुनाव के लिए 49 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की और अपनी चुनावी सहयोगी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) पर बिना कोई विचार-विमर्श किए 26 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का आरोप लगाया। वहीं माकपा ने दावा किया कि कांग्रेस के साथ चुनावी तालमेल को लेकर बातचीत अब भी जारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार साहा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सभी पहलुओं पर विचार करते हुए हमने अगरतला नगर निगम (एएमसी) चुनाव के लिए 49 उम्मीदवारों की घोषणा की है तथा दो और उम्मीदवारों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को एएमसी सहित 21 नागरिक निकायों के लिए 27 नवंबर को होने वाले चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल न करने की धमकियां दे रहे हैं। साहा ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम चुनाव लड़ेंगे। कुछ नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में हमारे उम्मीदवारों ने पहले ही नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं और बाकी बची सीटों के लिए नामांकन कल दाखिल किए जाएंगे। साहा ने माकपा पर आरोप लगाया कि उसने अगरतला नगर निगम के 26 वार्डों के लिए उम्मीदवार घोषित करने से पहले कांग्रेस के साथ कोई चर्चा नहीं की, जिसकी वजह से कांग्रेस को 49 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने पड़े। कांग्रेस के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए माकपा के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने कहा कि वामपंथी दल चाहते हैं कि भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस और अन्य भाजपा-विरोधी ताकतें निकाय चुनावों में एक साथ आएं। चौधरी ने कहा, मेरी मंगलवार रात कांग्रेस विधायक सुदीप रॉय बर्मन से बातचीत हुई थी और मैंने इस मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार साहा से भी बात की थी। हमने 26 वार्डों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की थी, जबकि बाकी सीटें विपक्षी गठबंधन इंडिया के तहत कांग्रेस के चुनाव लड़ने के लिए छोड़ दी थीं। उन्होंने कहा, कांग्रेस के साथ बातचीत अब भी चल रही है। वामपंथी दल चुनाव में भाजपा को किसी भी तरह का एकतरफा फायदा नहीं देना चाहते हैं।

तेजपुर कॉलेजिएट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को मिला पीएम श्री विद्यालय का दर्जा

गुवाहाटी (हिंस)। असम के ऐतिहासिक शिक्षण संस्थानों में शामिल तेजपुर कॉलेजिएट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) विद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मान्यता के साथ विद्यालय के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। इनमें टिंकरिंग लैब, पुस्तकालय तथा संगीत और खेलकूद के क्षेत्र में प्रतिभा विकसित करने के लिए नए अवसर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं से विद्यार्थियों के सीखने के अनुभव को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

राजस्थान : श्रीगंगानगर में रेल को बम से उड़ाने की साजिश नाकाम



जयपुर। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में रेलवे ट्रैक पर मंगलवार को जोरदार विस्फोट हुआ। यह घटना अनूपगढ़-सूरतगढ़ ट्रेन के गुजरने के तुरंत बाद हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विस्फोट से ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया। कोई हताहत की खबर नहीं है, क्योंकि विस्फोट ट्रेन के गुजरने के बाद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों और रेलवे अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विस्फोट का कारण और कोई साजिश की आशंका की जांच चल रही है। अधिकारियों ने कहा कि घटनास्थल की जांच के बाद ही पूरी जानकारी सामने आएगी। रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। एसपी हरिशंकर ने कहा कि मैंने और मेरी टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर लिया है, और रेलवे के अधिकारी भी वहां मौजूद हैं। हमारी फोरेंसिक टीम और बम निरोधक दस्ता रास्ते में हैं। उनके आने के बाद ही हम सही कारण बता पाएंगे; अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह कोई धमाका था या कुछ और। हम फिलहाल स्थिति का जायजा लेने के लिए घटनास्थल की जांच कर रहे हैं। जब्त किए गए आरडीएक्स से इसका कोई संबंध नहीं है।

पृष्ठ एक का शेष

पुलिस मुठभेड़ में ...

गोगोई ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया और शौच के बहाने से गाड़ी रुकवाकर हिरासत से भागने की कोशिश की। शिवसागर की पुलिस अधीक्षक पापोरी चेतिया ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े एक लंबित मामले में गुवाहाटी की अदालत से प्रोडक्शन वारंट मिलने के बाद, पुलिस गोगोई को जिले में ला रही थी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि उसे यहां लाते समय उसने अचानक भागने की कोशिश की। हाथापाई के दौरान उसने एक अधिकारी की सर्विस रिवॉल्वर छीनने का प्रयास किया। इसी बीच, सर्विस रिवॉल्वर से तीन गोलियां चलीं, जिससे हमारा एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया। एसएसपी ने कहा कि वह एक वांछित आरोपी था, इसलिए हमने एहतियाती कदम उठाए थे। हालांकि, उसके बर्ताव से अधिकारी की जान को खतरा पैदा हो गया था, खासकर इसलिए क्योंकि उसने पांच लोगों पर खुलेआम गोली चला दी थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि टीम के साथ मौजूद शिवसागर सदर पुलिस थाना प्रभारी के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (पीएसओ) को गोगोई को भागने से रोकने के लिए अपनी सर्विस गन का इस्तेमाल करना पड़ा। मुठभेड़ में शिवसागर टाउन पुलिस के सब-इंस्पेक्टर देबाशीष शर्मा भी घायल हो गए, जिन्हें शिवसागर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मालूम हो कि 26 अक्तूबर, 2026 की रात लगभग 9 बजे होटल विलास इन में गोलीबारी की घटना हुई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने रात लगभग 10 बजे आरोपी घनकांत को गिरफ्तार कर लिया था। इस गोलीबारी में भूदेव भराली (65), हेलेना भराली (58), देवर्षि कश्यप (39), रिनिकी कश्यप (30) और नारायण दास (48) की मौत हो गई थी। इसमें भूदेव भराली और नारायण दास का घर बरपेटा में है। वहीं, हेलेना भराली, देवर्षि कश्यप और रिनिका कश्यप फिलहाल गुवाहाटी के नवीन नगर के निवासी थे, हालांकि, वे भी मूल रूप से बरपेटा के ही रहने वाले थे। गोलीबारी में घायल हुए सत्येंद्र पाठक (43) बरपेटा के रहने वाले हैं। उनका फिलहाल गुवाहाटी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (जीएमसीएच) में इलाज चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने राहुल को ...

जी की क्या जरूरत है? आपकी मां और बहन भी पार्लियामेंट में हैं और जजों की कोई कमी नहीं है। भारत-यूएस डील पर बहस की गांधी की मांग पर निशाना साधते हुए, मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने प्रस्तावित चर्चा के आधार पर सवाल उठाया। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्लियामेंट में बहस में बोफोर्स स्कैंडल और भोपाल गैस ट्रेजेडी समेत कई मुद्दे शामिल हो सकते हैं। उन्होंने गांधी की राजनीतिक मुद्दों को सड़कों पर ले जाने की कथित कोशिशों पर भी सवाल उठाया और कहा कि यह बांग्लादेश या नेपाल नहीं है। डॉ. शर्मा ने गांधी के विदेश दौरों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनके कथित तौर पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन करने के बारे में भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मेरी बस एक रिक्वेस्ट है। आप एंग्री यंग मैन की तरह काम नहीं कर सकते। मैं आपको मुफ्त में सलाह दूंगा, अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, तो पार्लियामेंट में ठीक से बहस करें और शांति से करें। डॉ. शर्मा ने कहा कि आप सड़कों पर बहस चाहते हैं और हम पार्लियामेंट में चाहते हैं। अगली बार, दिवाली पर नहीं, वैलेंटाइन डे पर किसी को गुलाब दें। ज्ञात हो कि राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को खुली बहस के लिए दी गयी चुनौती के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने आज पलटवार किया है।

राज्य में 17 में से ...

प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य असम के विभिन्न हिस्सों में लोगों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती कैंसर उपचार उपलब्ध कराना है, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को इलाज के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों की यात्रा न करनी पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन अस्पतालों के माध्यम से राज्य में उन्नत कैंसर चिकित्सा सुविधाओं तक लोगों की पहुंच और मजबूत होगी।

श्रीनगर में आग लगने से 80 अस्थायी आश्रय स्थल राख, दो की मौत

श्रीनगर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात बेमिना इलाके के दुर्बल में आग लगने से लगभग 80 अस्थायी आश्रय स्थल जलकर राक हो गए। इस त्रासदी में दो लोगों की मौत हो गई। दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं। एक अधिकारी ने बताया कि आग रात करीब 12:23 बजे लगी और तेजी से अस्थायी आश्रय स्थलों में फैल गई। यह आश्रय स्थल तिरपाल और लकड़ी से बने थे। उन्होंने बताया कि आग की चपेट में आने से एक खाली पोल्ट्री फार्म और एक टिपर (ट्रक) को भी नुकसान पहुंचा है। इस अधिकारी ने बताया कि आग बुझाने के लिए जेबीसी और रावलपोरा फायर स्टेशनों की दमकल गाड़ियां और साथ ही बटामालू स्थित फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज मुख्यालय से अतिरिक्त मदद भेजी गई। अधिकारी ने कहा कि जब तक फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को सूचना मिली तब तक पूरा इलाका आग की लपटों में घिर चुका था।

दीवाली से पहले ईरान से आई अच्छी खबर

अब होर्मुज से बिना रोक-टोक गुजरेंगे भारतीय जहाज



नई दिल्ली। दीवाली से पहले ईरान से भारत के लिए अच्छी खबर आई है। ईरान ने भारत, चीन, इराक और कतर के जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने पर लगी पाबंदियों से छूट दे दी है। तेहरान का कहना है कि यह व्यवस्था आपसी हितों को ध्यान में रखकर की गई है, जिसमें भारत से दवाओं का आयात और चीन से मिलने वाला राजनीतिक समर्थन शामिल है। ईरान के एक वरिष्ठ सांसद ने बताया कि यह व्यवस्था इन चार देशों के साथ तेहरान के हितों से जुड़ी है। ऐसे समय में जब यह रणनीतिक जलमार्ग ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष में उलझा हुआ है, इस घोषणा से भारतीय शिपंग को कुछ राहत मिल सकती है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के उपाध्यक्ष, अमीर हयात मोकद्दम ने मंगलवार को *ईरानियन स्टूडेंट्स न्यूज एजेंसी* को दिए एक इंटरव्यू में इन छूटों के बारे में जानकारी दी। स्थानीय मीडिया के अनुसार, उन्होंने कहा कि हमने फिलहाल भारत, चीन, इराक और कतर को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने पर लगी पाबंदियों से छूट दी है। इन देशों के जहाज बिना किसी रोक-टोक के गुजर सकते हैं और अमेरिका भी उन्हें नहीं रोक सकता है। ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य तक पहुंच का इस्तेमाल कुछ चुनिंदा देशों के साथ अपने आर्थिक और राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कर रहा है, जबकि अन्य जहाजों पर पाबंदियां अभी भी लागू हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार, इस व्यवस्था के पीछे एक बड़ा कारण तेहरान की जरूरी दवाओं की जरूरत भी है। प्रतिबंधों और चल रहे संघर्षों के कारण, ईरान को कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और वित्तीय माध्यमों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भारत, जिसका दवा निर्माण क्षेत्र काफी बड़ा है, दवाओं और चिकित्सा उत्पादों का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है। भारतीय जहाजों को इस जलमार्ग से गुजरने की अनुमति देकर, तेहरान भारत से अपनी जरूरत का सामान आसानी से मंगा सकता है। वहीं, चीन के मामले में यह कदम मुख्य रूप से राजनीतिक लगता है।

असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने ग्वालपाड़ा में पदयात्रा में लिया हिस्सा

गुवाहाटी (हिंस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने देशभर में बढ़ते राजनीतिक विरोध-प्रदर्शनों और आंदोलनों के बीच अपने *लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ* अभियान के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इस अभियान के तहत असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को बिहार में आयोजित *लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ* पदयात्रा में हिस्सा लिया। उनकी भागीदारी को राज्य की सीमाओं से आगे बढ़कर पार्टी के राजनीतिक संदेश को राष्ट्रीय स्तर पर लोगों तक पहुंचाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। वहीं, असम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने भी बुधवार को ग्वालपाड़ा जिले में आयोजित इसी अभियान की पदयात्रा में हिस्सा लिया। भाजपा की ओर से आज जारी बयान में कहा गया है कि



इस अभियान का उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। पार्टी ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर अराजकता और राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना उचित नहीं है। भाजपा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि लोकतंत्र की रक्षा की बात करने वाली कांग्रेस का राजनीतिक नेतृत्व लंबे समय से एक परिवार तक सीमित रहा है। पार्टी ने कांग्रेस के आंतरिक लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल उठाते हुए कहा कि संगठन में जमीनी स्तर पर भागीदारी और नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। भाजपा ने कहा कि राजनीतिक मतभेदों को सार्वजनिक व्यवस्था और सामाजिक स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों के बजाए लोकतांत्रिक बहस, रचनात्मक संवाद और संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यक्त किया जाना चाहिए। पार्टी के अनुसार, *लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ* अभियान का उद्देश्य जिम्मेदार राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, कानून के शासन को मजबूत करना और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास बनाए रखना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और पूर्वोत्तर में शिक्षा के विकास पर मंथन



गुवाहाटी (हिंस)। असम के स्वास्थ्य मंत्री अशोक सिंघल ने बुधवार को प्रागज्योतिषपुर विश्वविद्यालय में आयोजित *उत्तर-पूर्व शिक्षा सम्मेलन* में हिस्सा लिया। सम्मेलन में देश की शिक्षा व्यवस्था के भविष्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन और पूर्वोत्तर क्षेत्र में शैक्षणिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। सिंघल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सम्मेलन की झलकियां साझा करते हुए कहा कि उन्हें *राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का क्रियान्वयन : कार्यान्वयन से उत्कृष्ट परिणाम तक* विषय पर आयोजित चर्चा और विचार-विमर्श में शामिल होकर खुशी हुई। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को केवल लागू करने तक सीमित न रखते हुए गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया। मंत्री ने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र के भविष्य के निर्माण का भी प्रमुख आधार है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, कौशल आधारित और विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करना आवश्यक है। उन्होंने पूर्वोत्तर की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा नई पीढ़ी के लिए ज्ञान, कौशल और संभावनाओं के नए अवसर खोलने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस अवसर पर असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और सांसद बिजुली कलिता मेधी भी उपस्थित थीं।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हिमंत विश्व शर्मा को भेंट की मधुबनी पेंटिंग

गुवाहाटी (हिंस)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आत्मीय मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए कहा कि बिहार और असम के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं। असम में रहने वाला बिहारी समुदाय राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देता आया है। उन्होंने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की पहचान मधुबनी चित्रकला की एक कलाकृति उपहार स्वरूप भेंट की। शर्मा ने इस उपहार के लिए सम्राट चौधरी



का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मधुबनी चित्रकला मिथिला की जीवनशैली, परंपराओं और आध्यात्मिकता को रंगों एवं बारीक कलाकारी के माध्यम से जीवंत रूप प्रदान करती है। यह भारतीय लोक कला को विशिष्ट पहचान देती है। उन्होंने कहा कि मधुबनी चित्रकला के रूप में मिला यह उपहार बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और असम के साथ उसकी आत्मीयता का सुंदर प्रतीक है। शर्मा ने कहा कि दोनों राज्यों की विकास यात्रा डबल इंजन की गति से आगे बढ़ रही है। उन्होंने मां कामाख्या से प्रार्थना की कि आने वाले वर्षों में बिहार और असम समृद्धि के नए शिखरों को छुएं।

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा जरूरी : राज्यपाल

गुवाहाटी (हिंस)। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने बुधवार को गुवाहाटी स्थित प्रागज्योतिषपुर विश्वविद्यालय में तीसरे पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और समग्र शिक्षा व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को साकार करना : क्रियान्वयन से बेहतर परिणाम तक* विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों के कुलपति, निदेशक, प्राचार्य, शिक्षाविद और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन और इसके बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने



का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के चरित्र निर्माण, समाज को मजबूत बनाने और राष्ट्र के विकास की आधारशिला भी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में ज्ञान, मूल्यों, रचनात्मकता, अनुशासन और चरित्र निर्माण को समान महत्व दिया जाना चाहिए। आचार्य ने पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, बौद्धिक क्षमता और प्राकृतिक संपदा का उल्लेख करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व वाली असम सरकार की ओर से मेडिकल कॉलेजों, इंजीनियरिंग संस्थानों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयासों की सराहना की। राज्यपाल ने ग्रामीण, जनजातीय, दूरदराज और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समान पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बालिका शिक्षा, तकनीकी कौशल और नेतृत्व विकास को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने शिक्षाविदों से पूर्वोत्तर की विशिष्ट चुनौतियों और संभावनाओं पर विचार-विमर्श करने का आग्रह किया। इनमें बार-बार आने वाली बाढ़, जलवायु परिवर्तन, कृषि उत्पादकता, चाय उद्योग का आधुनिकीकरण, औषधीय पौधों पर अनुसंधान और जैव विविधता का संरक्षण प्रमुख हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अशोक सिंघल ने घोषणा की कि प्रागज्योतिषपुर विश्वविद्यालय में चालू शैक्षणिक सत्र से प्रागज्योतिषपुर आयुर्वेद गुरुकुलम की शैक्षणिक गतिविधियां शुरू होंगी। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त यह कार्यक्रम देश के केवल पांच संस्थानों में संचालित होगा। पूर्वोत्तर में प्रागज्योतिषपुर विश्वविद्यालय एकमात्र संस्थान होगा, जहां यह शिक्षा उपलब्ध होगी। उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय शिक्षा नीति समीक्षा समिति के अध्यक्ष एवं प्रख्यात शिक्षाविद प्रो. एम. जगदीश कुमार, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. कैलाश चंद्र शर्मा, कुलपति प्रो. राघवेन्द्र पी. तिवारी, कुलसचिव डॉ. देबब्रत खनिकर सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

पारिवारिक कलह में पति ने की पत्नी की हत्या, खुद फंदे से लटका

रंगिया (विभास)। असम के रंगिया अंतर्गत बरदोंगा-बटाकुची क्षेत्र के इस्लामपुर सुबुरी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मंगलवार की रात एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद, बुधवार सुबह आरोपी पति का शव भी एक पेड़ से फंदे पर लटका हुआ बरामद किया गया। इस दोहरे हादसे से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बरदोंगा-बटाकुची (इस्लामपुर सुबुरी) निवासी इमदाद अली और उसकी 40 वर्षीय पत्नी माबियारा बेगम के बीच मंगलवार रात किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई थी। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर इमदाद अली ने धारदार हथियार से प्रहार कर अपनी पत्नी की बेरहमी से जान ले ली। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। घटना की सूचना मिलते ही रंगिया थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, महिला के शव को अपने कब्जे में लिया और मामले की शुरुआती जांच शुरू कर दी। पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही थी। इसी बीच, बुधवार सुबह रंगिया के कलमोनी इलाके में एक खुले मैदान के पास पेड़ से फंदे



पर लटके हुए इमदाद अली का शव मिला। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से पति-पत्नी के बीच अक्सर पारिवारिक कलह और कहासुनी होती रहती थी। आशंका जताई जा रही है कि इसी मानसिक तनाव और आवेश में आकर पति ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल, रंगिया पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना के वास्तविक कारणों का गहराई से पता लगाने के लिए आगे की कानूनी जांच शुरू कर दी है।

दैमारी ने रेशम उत्पादन के उप-उत्पादों पर राष्ट्रीय सम्मेलन में लिया हिस्सा

गुवाहाटी (हिंस)। असम के हथकरघा, वस्त्र एवं रेशम उत्पादन मंत्री बिस्वजीत दैमारी ने बुधवार को गुवाहाटी के नेडफी हाउस में आयोजित एसईआरआई-बेस्ट 2026 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। यह राष्ट्रीय सम्मेलन रेशम उत्पादन से जुड़े उप-उत्पादों, उद्यमिता और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित है। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के अधीन केंद्रीय रेशम बोर्ड के अंतर्गत केंद्रीय मूगा एवं एरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीएमईआरएंडटीआई), लाहदोईगढ़, जोरहाट की ओर से किया गया। इसमें देशभर के शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, रेशम उत्पादन विशेषज्ञों, उद्यमियों, उद्योग प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित पक्षों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्री बिस्वजीत दैमारी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। संस्थान के निदेशक डॉ. कार्तिक नियोग ने स्वागत भाषण दिया। अपने संबोधन में दैमारी ने असम के पारंपरिक मूगा और एरी रेशम उद्योग की अपार संभावनाओं को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि रेशम उत्पादन को केवल पारंपरिक रेशम निर्माण तक सीमित रखने के बजाए इससे प्राप्त होने वाले उप-उत्पादों के आर्थिक उपयोग पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे उद्यमिता के नए अवसर पैदा होने के साथ-साथ रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। उन्होंने उप-उत्पादों के बेहतर इस्तेमाल के लिए आधुनिक एवं टिकाऊ तकनीकों को अपनाने पर भी जोर दिया। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में *बाय-प्रोडक्ट्स ऑफ सेरीकल्चर* नामक पुस्तक का विमोचन किया गया।

कामरूप में सात दिनों के भीतर बंद जलापूर्ति योजनाओं को चालू करने का निर्देश, लापरवाही बर्दाश्त नहीं : कृष्णेंदु पाल



गुवाहाटी (हिंस)। असम के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कृष्णेंदु पाल ने कामरूप जिले में बंद पड़ी सभी पेयजल आपूर्ति योजनाओं को अगले सात दिनों के भीतर चालू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने बुधवार को कामरूप जिले के ददरा स्थित भृगु कुमार फूकन सभागार में जल जीवन मिशन (जेजेएम 2.0) और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी 2.0) की प्रगति एवं कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए। बैठक में गुवाहाटी डिवीजन-1 और रंगिया डिवीजन के अंतर्गत आने वाली पेयजल आपूर्ति योजनाओं की स्थिति, प्रत्येक परिवार तक गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाने, बंद पड़ी योजनाओं को पुन: चालू करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। पाल ने कहा कि कामरूप जिले के प्रत्येक परिवार को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना और ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को स्थानीय विधायकों, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और आम लोगों को साथ लेकर योजनाओं का काम तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में गुवाहाटी की सांसद बिजुली कलिता मेधी तथा विधायक राजू मेस, प्रकाश चंद्र दास और हिमांशु शेखर बैश्य उपस्थित रहे। इसके अलावा कामरूप जिला परिषद के अध्यक्ष निपन भुइयां, जिला आयुक्त देव कुमार मिश्र, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ गोस्वामी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता (जल) भास्कर ज्योति शर्मा और मुख्य अभियंता (स्वच्छता) रम्य ज्योति शर्मा सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि और पंचायत सचिव भी बैठक में शामिल हुए।

फकीराग्राम में कृषि उपकरण एवं अन्य सामग्री वितरित



कोकराझाड़ (हिंस)। कोकराझाड़ जिला के फकीराग्राम अंतर्गत भोटगांव में फकीराग्राम परिषद निर्वाचन क्षेत्र के पार्षद एजामुल हक की पहल पर वीसीडीसी के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों के बीच कृषि उपकरण एवं विभिन्न उपयोगी सामग्रियों का वितरण किया गया। इस दौरान लाभार्थियों को कृषि कार्य में उपयोग के लिए स्प्रे मशीन, छाता तथा मच्छरदानी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में फकीराग्राम नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष सुल्तान आलम सहित पार्टी के कई नेता एवं कार्यकर्ता तथा स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस पहल का उद्देश्य किसानों को कृषि कार्यों में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के साथ-साथ आम लोगों की दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहायता करना है। पार्षद एजामुल हक ने उम्मीद जताई कि इस प्रकार की जनकल्याणकारी पहल से किसानों एवं लाभार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा और उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा।

पीड़ित परिवार से मिले गौरव गोगोई, घनकांत के साथ अन्य लोगों की संलिप्तता का जताया संदेह

गुवाहाटी (हिंस)। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने बुधवार को बरपेटा स्थित भराली परिवार के आवास पर पहुंचकर होटल विलास इन गोलीकांड में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस दौरान गौरव गोगोई ने कहा कि इस वारदात में मुख्य आरोपी घनकांत गोगोई अकेले शामिल नहीं था। उन्होंने घटना में अन्य लोगों की संलिप्तता की आशंका जताते हुए पूरे मामले की जांच पर सवाल उठाए। दूसरी ओर, कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता देबब्रत सैकिया ने कहा कि कांग्रेस कभी भी न्यायिक प्रक्रिया से बाहर की गई हत्या का समर्थन नहीं करती है। उन्होंने कहा कि घनकांत गोगोई की हत्या के बाद कई सवाल अनुत्तरित रह गए हैं। सैकिया ने कहा कि उसकी मौत के बाद कई महत्वपूर्ण बातें सामने नहीं आ सकीं।

कोकराझाड़ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की प्लेटिनम जुबली समारोह

कोकराझाड़ (हिंस)। कोकराझाड़ शहर के प्रतिष्ठित एवं ऐतिहासिक शिक्षण संस्थानों में से एक पीएम श्री कोकराझाड़ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ने अपनी गौरवशाली शैक्षणिक यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में विद्यालय प्लेटिनम जुबली समारोह मनाने के गौरवपूर्ण अवसर पर पहुंच गया है। शिक्षा के माध्यम से समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के उद्देश्य से स्थापित इस विद्यालय की 75 वर्षों की यात्रा केवल एक शिक्षण संस्थान की उपलब्धियों की कहानी नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र में महिला शिक्षा के विस्तार, सामाजिक परिवर्तन और शैक्षणिक विकास के इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण अध्याय है। स्थापना काल से ही विद्यालय ने कोकराझाड़ सहित आसपास के क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्राओं के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक समय ऐसा भी था, जब महिला शिक्षा को लेकर समाज में अनेक चुनौतियां और सीमाएं मौजूद थीं। ऐसे कठिन दौर में भी विद्यालय ने बालिकाओं को शिक्षा का अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किया। बीते सात दशकों से अधिक की इस शैक्षणिक यात्रा के दौरान विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर निकली असंख्य छात्राओं ने आज



समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा, योग्यता, मेहनत और कार्यकुशलता के बल पर विशिष्ट पहचान स्थापित की है। विद्यालय की पूर्व छात्राओं की उपलब्धियां न केवल संस्थान के लिए गर्व का विषय हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनी हुई हैं। प्लेटिनम जुबली के इस ऐतिहासिक अवसर पर विद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महान व्यक्तित्वों को श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। इसके साथ ही विद्यालय के शैक्षणिक विकास और प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना अमूल्य योगदान देने वाले सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं, कर्मचारियों तथा शुभचिंतकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जा रही है। वहीं, विद्यालय की पूर्व छात्राओं की स्मृतियां, अनुभव और जीवन की सफलताएं इस गौरवपूर्ण आयोजन को और भी यादगार एवं अर्थपूर्ण बना रही हैं। 75 वर्षों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि को लेकर पूर्व एवं वर्तमान छात्राओं, शिक्षक-शिक्षिकाओं, अभिभावकों, पूर्व विद्यार्थियों और शुभचिंतकों के बीच उत्साह, उल्लास और भावनात्मक जुड़ाव का माहौल बना हुआ है। निस्संदेह, पीएम श्री कोकराझाड़ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की यह प्लेटिनम जुबली केवल अतीत की उपलब्धियों का उत्सव नहीं, बल्कि महिला शिक्षा को और अधिक सशक्त बनाने तथा उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के प्रति नई प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है।

रंगिया में *अंतर-सीमांत एंटी-सबोटाज चेक प्रतियोगिता 2026* का भव्य समापन, गुवाहाटी सीमांत रहा विजेता

रंगिया (विभास)। सशस्त्र सीमा बल के क्षेत्रक मुख्यालय रंगिया के प्रशासनिक भवन परिसर में आयोजित तीन दिवसीय *अंतर-सीमांत एंटी-सबोटाज चेक प्रतियोगिता-2026* का बुधवार को हर्षोल्लास के साथ समापन हुआ। प्रतियोगिता में सशस्त्र सीमा बल के कुल छह सीमांत मुख्यालयों-गुवाहाटी, पटना, सिलीगुड़ी, रानीखेत, तेजपुर और लखनऊ की टीमों ने पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ भाग लिया। उत्कृष्ट समग्र प्रदर्शन के आधार पर सीमांत गुवाहाटी ने प्रथम स्थान प्राप्त कर विजेता ट्रॉफी अपने नाम की, जबकि सीमांत पटना उपविजेता रहा। समारोह के मुख्य अतिथि सीमांत मुख्यालय गुवाहाटी के महानिरीक्षक सुधीर वर्मा थे। उनके मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रतियोगिता के आधिकारिक शुभंकर *प्रखर* की विशेष उपस्थिति ने सबका ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर क्षेत्रक मुख्यालय रंगिया के उप-महानिरीक्षक मनोज कुमार और क्षेत्रक मुख्यालय बंगाईगांव के उप-महानिरीक्षक सुदीप्ता दास, आईपीएस सहित विभिन्न सीमाओं से आए टीम मैनेजर, प्रतिभागी और एसएसबी के कई वरिष्ठ अधिकारी व कार्मिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक स्वागत, अभिनंदन और जोश से भरपूर एसएसबी गीत के गायन के साथ हुई। क्षेत्र मुख्यालय के डीआईजी द्वारा स्वागत संबोधन



और प्रतियोगिता की रूपरेखा प्रस्तुत किए जाने के बाद, मुख्य अतिथि ने विजेता एवं उपविजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। अपने समापन संबोधन में महानिरीक्षक सुधीर वर्मा ने प्रतिभागियों के प्रदर्शन की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं कार्मिकों की व्यावसायिक दक्षता और परिचालन तैयारियों को बेहतर बनाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को उच्च कोटि की व्यावसायिक दक्षता, अनुशासन और टीम भावना के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

संपादकीय

ईरान पर 'परमाणु हमला'

नौवीं बार संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अमरीका ईरान पर 'परमाणु हमला' कर सकता है! राष्ट्रपति ट्रंरप इजरायल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लगातार दबाव में हैं कि परमाणु हमले से ही 'ईरान समस्या' का कोई समाधान मिल सकता है। यदि ईरान पर परमाणु हमला किया गया, तो उसके बाद तीसरे विश्व युद्ध की स्थितियां 'चरम' पर होंगी। रूस, उत्तरी कोरिया, चीन और भारत भविष्य के विनाशकारी युद्ध में शामिल होने को बाध्य होंगे! लेकिन राष्ट्रपति ट्रंरप ईरान युद्ध के 8 लंबे महीनों के बाद भी दोहरी जुबान बोल रहे हैं कि ईरान के साथ 'डील' की बातचीत अच्छी चल रही है। वह युद्ध नहीं चाहते, लेकिन फिर यह भी बयान देते हैं कि हम ईरान का अस्तित्व खत्म कर देंगे। अमरीका में मध्यावधि चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं, लिहाजा अब राष्ट्रपति ट्रंरप के लिए दोनों ही विकल्प खुले हैं कि ईरान पर एक बार फिर युद्ध थोपा जाए अथवा समझौते की संभावनाओं को पुख्ता किया जाए। इसी दौरान अमरीका के वरिष्ठ पत्रकार और कभी राष्ट्रपति ट्रंरप के बेहद करीब रहे टकर कार्लसन ने 'एक्स' प्लेटफॉर्म पर पोस्ट लिखी है कि अमरीका कुछ ही दिनों में ईरान के नतांज परमाणु केंद्र के करीब 'पिकएक्स पहाडियों' पर परमाणु हमला कर सकता है। इस बार 'बी 61-11' बॉम्बर्स के जरिए 'बंकरफोड़' बमबारी की जा सकती है या मिसाइलों से हमला किया जा सकता है! अमरीका पहले भी ईरान के परमाणु केंद्रों की पहाडियों पर हमले कर चुका है, लेकिन इस बार 'परमाणु सम्मत हथियारों' से हमले की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दिलचस्प यह है कि उपराष्ट्रपति वेंस और ट्रंरप के 'विशेष दूत' स्टीव विटकॉफ युद्ध नहीं, ईरान के साथ बातचीत और डील के पक्षधर हैं। बहरहाल यदि इस बार युद्ध का विस्तार हुआ, तो कच्चे तेल की कीमतें 140 डॉलर प्रति बैरल तक उछल सकती हैं और फिर वहीं स्थिर रह सकती हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। अमरीका और यूरोपीय देशों में खासकर गैस की मांग 'चरम' पर पहुंच जाती है, क्योंकि वहां के घरों को गर्म रखने के लिए गैस की बुनियादी जरूरत होती है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक, 15 देशों में ऊर्जा की जबरदस्त किल्लत है। गैस के साथ-साथ तेल के संकट भी हैं। फ्रांस, फिलीपींस, इंडोनेशिया, स्लोवाकिया, जापान सरीखे देशों में 'ऊर्जा आपातकाल' और 'राशनिंग' की व्यवस्था लागू करनी पड़ी है। जहां तक भारत का सवाल है, तो उसने अक्तूबर माह में 56 लाख बैरल तेल औसतन हररोज खरीदा है। सुखद संकेत यह है कि खाड़ी देशों से औसतन रोजाना 23 लाख बैरल तेल हररोज आयात किया जा सका है और 20 लाख बैरल तेल रूस से खरीदा है। भारत कुछ अन्य देशों से भी सीमित मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है। यदि ईरान युद्ध नए सिरे से भड़कता है, तो होर्मुज के रास्ते आयात फिर बंद हो सकता है। सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हूती आतंकी लगातार हमले कर रहे हैं। रूस पर यूक्रेन ने इतने हमले किए हैं कि उसके 49 फीसदी तेल संयंत्र, रिफाइनरियां, तेल के संसाधन नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। रूस से हमें नवंबर-दिसंबर में तेल की आपूर्ति निश्चित रूप से कम होगी! यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 140 डॉलर या अधिक रहीं, तो भारत में मुद्रास्फीति, आम वस्तुओं के महंगे दाम, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी और 'रुपए' के अवमूल्यन की स्थितियां लगातार बनेंगी। नतीजतन भारत की आर्थिक विकास दर 7 फीसदी से कम हो सकती है। बहरहाल अमरीका के ईरान पर संभावित परमाणु हमले की समूचे देश में यह 'सामूहिक प्रतिक्रिया' सामने आ रही है कि ईरान परमाणु अप्रसार संधि से बाहर आए और अपनी परमाणु नीति में बदलाव करे। अर्थात परमाणु बम बनाए। ईरान के पास जितना यूरेनियम सर्वंधित है, उससे कुछ ही दिनों में 10-12 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं।

> अमरीका और यूरोपीय देशों में खासकर गैस की मांग 'चरम' पर पहुंच जाती है, क्योंकि वहां के घरों को गर्म रखने के लिए गैस की बुनियादी जरूरत होती है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक, 15 देशों में ऊर्जा की जबरदस्त किल्लत है। गैस के साथ-साथ तेल के संकट भी हैं। फ्रांस, फिलीपींस, इंडोनेशिया, स्लोवाकिया, जापान सरीखे देशों में 'ऊर्जा आपातकाल' और 'राशनिंग' की व्यवस्था लागू करनी पड़ी है। जहां तक भारत का सवाल है, तो उसने अक्तूबर माह में 56 लाख बैरल तेल औसतन हररोज खरीदा है। सुखद संकेत यह है कि खाड़ी देशों से औसतन रोजाना 23 लाख बैरल तेल रूस से खरीदा है। भारत कुछ अन्य देशों से भी सीमित मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है। यदि ईरान युद्ध नए सिरे से भड़कता है, तो होर्मुज के रास्ते आयात फिर बंद हो सकता है। सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हूती आतंकी लगातार हमले कर रहे हैं। रूस पर यूक्रेन ने इतने हमले किए हैं कि उसके 49 फीसदी तेल संयंत्र, रिफाइनरियां, तेल के संसाधन नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। रूस से हमें नवंबर-दिसंबर में तेल की आपूर्ति निश्चित रूप से कम होगी! यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 140 डॉलर या अधिक रहीं, तो भारत में मुद्रास्फीति, आम वस्तुओं के महंगे दाम, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी और 'रुपए' के अवमूल्यन की स्थितियां लगातार बनेंगी। नतीजतन भारत की आर्थिक विकास दर 7 फीसदी से कम हो सकती है। बहरहाल अमरीका के ईरान पर संभावित परमाणु हमले की समूचे देश में यह 'सामूहिक प्रतिक्रिया' सामने आ रही है कि ईरान परमाणु अप्रसार संधि से बाहर आए और अपनी परमाणु नीति में बदलाव करे।

पर्यावरण संरक्षण किसी व्यक्ति, दल या धर्म की जागीर नहीं, बल्कि समूचे समाज की साझा जिम्मेदारी

प्रदूषण पर राजनीति का धुआं और जनता की घुटती सांसें

त्योहार खुशियां बांटने के लिए होते हैं, सांसों में जहर घोलने के लिए नहीं। दीपावली प्रकाश, प्रसन्नता, उल्लास और मंगलकामना का पर्व है, लेकिन यदि उत्सव की चमक के पीछे आसमान धुएं से भर जाए, बच्चों और बुजुर्गों का दम घुटने लगे तथा आम आदमी स्वच्छ हवा के लिए तरसने लगे तो हमें अपनी उत्सव परंपराओं और सामाजिक जिम्मेदारियों पर गंभीरता से विचार करना होगा। विडंबना यह है कि आज प्रदूषण जैसी जीवन-मरण की समस्या पर भी राजनीति का धुआं छाने लगा है। जब लोगों की सांसें संकट में हों, तब धर्म, जाति और राजनीतिक विचारधाराओं के चश्मे से समस्या को देखना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि सामाजिक संवेदनहीनता का प्रमाण भी है। अभिनेत्री और पर्यावरण कार्यकर्ता दीया मिर्जा ने पटाखों से होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने अपने पर्यावरण अनुकूल दीपावली अभियान में उनका वीडियो जारी किया, लेकिन राजनीतिक विवाद के बाद उसे हटा दिया गया। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाना आखिर विवाद का विषय कैसे बन गया? किसी कलाकार का पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में बोलना किसी धर्म या त्योहार का विरोध कैसे हो सकता है? मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा वीडियो दोबारा जारी करने का निर्देश इस बात का संदेश है कि जनहित की आवाज को राजनीतिक दबाव के आगे दबाया नहीं जाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण किसी व्यक्ति, दल या धर्म की जागीर नहीं, बल्कि समूचे समाज की साझा जिम्मेदारी है। मुंबई का उदाहरण इस समस्या की गंभीरता को और उजागर करता है। सामान्यतः समुद्र की हवाओं और भौगोलिक स्थिति के कारण मुंबई को दिल्ली की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर वायु संचार का लाभ मिलता है, लेकिन अब वहां भी प्रदूषण का संकट गहराने लगा है। बीएमसी की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार, मुंबई के 14 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से 13 पर पीएम-10 का वार्षिक औसत स्तर राष्ट्रीय निर्धारित सीमा 60 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर से अधिक पाया गया। चेंबूर और बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में यह स्तर 125 माइक्रोग्राम तक पहुंच गया। यह केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि महानगरीय विकास की उस दिशा पर प्रश्नचिह्न है जिसमें इमारतें तो ऊंची होती जा रही हैं, लेकिन लोगों के हिस्से की स्वच्छ हवा छोटी होती जा रही है। यह समझना आवश्यक है कि मुंबई हो या दिल्ली, प्रदूषण का पूरा दोष केवल दीपावली के पटाखों पर डालकर हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। निर्माण स्थलों से उड़ती धूल, सड़कों पर जमा मिट्टी, वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, कचरा जलाना और कमजोर शहरी नियोजन इसके बड़े कारण हैं। पटाखे प्रदूषण की समस्या को त्योहारों के दौरान और गंभीर बनाते हैं, लेकिन प्रदूषण का स्रोत वर्षभर सक्रिय रहता है। इसलिए केवल दीपावली के आसपास प्रतिबंध लगाना और फिर शेष वर्ष आंखें मूंद लेना समस्या का समाधान नहीं, बल्कि मौसमी सक्रियता का प्रदर्शन है। मुंबई में 13 निगरानी केंद्रों का राष्ट्रीय मानक से ऊपर होना बताता है कि समुद्री हवाओं के भरोसे पर्यावरण की रक्षा नहीं की जा सकती।



दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की स्थिति तो और भी चिंताजनक है। सर्दियों की शुरुआत होते ही तापमान में गिरावट, हवा की धीमी गति और वातावरण में प्रदूषकों के ठहराव से वायु गुणवत्ता तेजी से बिगड़ती है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के नागरिक हर वर्ष इस जहरीले वातावरण का सामना करते हैं। सुबह की सैर स्वास्थ्य का माध्यम बनने के बजाय जोखिम बन जाती है। बच्चों को खांसी, बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी और पहले से बीमार लोगों को अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जिस हवा में जीवन का संगीत होना चाहिए, उसमें जब प्रदूषण का जहर घुल जाए तो विकास के तमाम दावे बेमानी लगने लगते हैं। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में दीपावली के अवसर पर केवल प्रमाणित हरित पटाखों की सीमित बिक्री और निर्धारित समय में उनके उपयोग की अस्थायी अनुमति दी है। 7 और 8 नवंबर के लिए निर्धारित समय सुबह 6 से 7 बजे तथा रात 8 से 10 बजे है। इसके बाद 9 नवंबर से पूर्ण प्रतिबंध फिर प्रभावी होना है। न्यायालय ने नियमों के उल्लंघन और पारंपरिक पटाखों को हरित पटाखों के नाम पर बेचने से रोकने के लिए सख्त निगरानी पर भी जोर दिया है। लेकिन प्रश्न यह है कि आदेश कागज पर सख्त और सड़कों पर बेअसर क्यों रह जाते हैं? हरित पटाखों की आड़ में पारंपरिक पटाखों की बिक्री, निर्धारित समय के बाद आतिशबाजी और प्रतिबंधित सामग्री का खुलेआम कारोबार प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोलता है। कानून बनाना पर्याप्त नहीं, उसका निष्पक्ष और कठोर क्रियान्वयन भी जरूरी है। यदि नियम तोड़ने वालों को राजनीतिक संरक्षण या प्रशासनिक उदासीनता का लाभ मिलता रहा तो न्यायालयों के निर्देश भी धुएं में उड़ते रहेंगे। दीपावली के उत्सव को सीमित पटाखों, सामूहिक आतिशबाजी और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों के साथ भी पूरे उल्लास से मनाया जा सकता है। उत्सव की सार्थकता शोर की तीव्रता में नहीं, बल्कि मन की प्रसन्नता और सामाजिक सद्भाव में है। यह किसी की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार का सम्मान है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब दीया मिर्जा जैसी अभिनेत्री पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती हैं तो उनके संदेश को राजनीतिक विवाद में उलझा दिया जाता है। मुंबई उच्च न्यायालय ने 3 नवंबर को बीएमसी को उनका हटाया गया वीडियो दोबारा अपलोड करने का निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि पर्यावरण के मुद्दे को राजनीतिक या सांप्रदायिक रंग देना अनुचित है। न्यायालय की यह टिप्पणी हमारे लोकतांत्रिक विवेक को झकझोरने वाली है। आज आवश्यकता है कि सरकारें, न्यायपालिका, नगर निकाय, राजनीतिक दल, उद्योग जगत, सामाजिक संगठन और आम नागरिक एक साझा संकल्प के साथ आगे आएं। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण हो, वाहनों के उत्सर्जन पर कठोर निगरानी हो, सार्वजनिक परिवहन मजबूत बने, कचरा जलाने पर रोक लगे और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की जवाबदेही तय हो। साथ ही नागरिक भी पटाखों के अनावश्यक उपयोग, कचरा जलाने और निजी वाहनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से बचें। अंततः सवाल यह नहीं है कि दीपावली पर पटाखे चलें या न चलें, सवाल यह है कि क्या हम आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और सुरक्षित जीवन दे पाएंगे? राजनीति की अपनी जगह है, धर्म और परंपराओं का अपना महत्व है, लेकिन जीवन से बड़ा कोई उत्सव और स्वास्थ्य से बड़ी कोई परंपरा नहीं हो सकती। याद रखना होगा कि प्रदूषण किसी की जाति, धर्म, भाषा या राजनीतिक विचारधारा देखकर फेफड़ों में प्रवेश नहीं करता। हवा सबकी साझा है और उसका संकट भी सबका साझा संकट है।

> विडंबना यह है कि आज प्रदूषण जैसी जीवन-मरण की समस्या पर भी राजनीति का धुआं छाने लगा है। जब लोगों की सांसें संकट में हों, तब धर्म, जाति और राजनीतिक विचारधाराओं के चश्मे से समस्या को देखना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि सामाजिक संवेदनहीनता का प्रमाण भी है। अभिनेत्री और पर्यावरण कार्यकर्ता दीया मिर्जा ने पटाखों से होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने अपने पर्यावरण अनुकूल दीपावली अभियान में उनका वीडियो जारी किया, लेकिन राजनीतिक विवाद के बाद उसे हटा दिया गया। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाना आखिर विवाद का विषय कैसे बन गया? किसी कलाकार का पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में बोलना किसी धर्म या त्योहार का विरोध कैसे हो सकता है? मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा वीडियो दोबारा जारी करने का निर्देश इस बात का संदेश है कि जनहित की आवाज को राजनीतिक दबाव के आगे दबाया नहीं जाना चाहिए।

देश दुनीया से

महारैली की भीड़ ही नहीं मुद्दों को भी देखिए

मुद्दा महत्वपूर्ण होता है अथवा कोई मुद्दा उठाने वालों की संख्या? राजधानी दिल्ली में हुई विपक्ष की 'महारैली' के संदर्भ में यह सवाल उठाया जा रहा है। यह सही है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन 'इंडिया' ने दावा किया था कि 'लोकतंत्र बचाओ' वाले इस अभियान में देशभर से दस लाख नागरिक राजधानी में एकत्र होंगे। यह भी सही है कि सारी गणनाएं बता रही हैं कि उस दिन दिल्ली में देश भर से आने वालों की संख्या दस लाख नहीं थी। प्रदर्शन में शामिल होने वालों को किसी ने गिना नहीं, यह संभव भी नहीं होता। इस गणना के हमेशा अनुमान ही लगाए जाते हैं। 'महारैली' आयोजित करने वाले लाखों की उपस्थिति के अपने दावे पर अड़े हुए हैं और भाजपा के सारे नेता इस संख्या को सत्ताईस हजार से लेकर सत्तर हजार तक बताने में लगे हैं। प्रदर्शन करने वालों की संख्या कुछ भी हो, यह स्पष्ट दिख रहा है कि सत्तारूढ़ पक्ष इस 'भारी जमावड़े' से कुछ विचलित है। जिस तेजी से भाजपा के नेता देश भर में 'अराजकता हटाओ' की अपनी मुहिम में लग गए हैं, वह यह बताने के लिए पर्याप्त है कि 'लोकतंत्र बचाओ' का मुद्दा देश की राजनीति को कहीं गहरे तक प्रभावित कर रहा है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि राजधानी में हुए इस प्रदर्शन में कितने हजार या कितने लाख लोग शामिल हुए थे, महत्वपूर्ण वह मुद्दा है जो प्रदर्शनकारी उठा रहे थे। मुद्दा कथित वोट चोरी का था और इस प्रदर्शन से विपक्ष इसे देशव्यापी जन-आंदोलन बनाने का प्रयास कर रहा था। इस प्रयास की सफलता का आकलन भी तत्काल संभव नहीं है, पर इतना अवश्य स्पष्ट हो गया है कि लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर विपक्ष का चलाया जाने वाला यह अभियान जनता की चिंता का विषय बनने लगा है। सत्तारूढ़ पक्ष भले ही कुछ भी कहता रहे, पर विपक्ष की राजनीतिक सक्रियता और कार्यकर्ताओं का जोश इसे बहुत हद तक सफल बता रहा है। सफल इस माने में कि आम मतदाता भी इस बारे में सोचने लगा है कि 'वोट चोरी' के आरोप में कहीं कुछ गंभीरता है। यह सही है कि ऐसी स्थितियों में तत्काल परिणाम सामने नहीं आते, पर ऐसे प्रयास आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने लगते हैं। विपक्ष ने अपने इस प्रयास को 'लोकतंत्र बचाओ' का नाम दिया है। उसका आरोप है कि सत्तारूढ़ पक्ष 'बेईमानी' से सत्ता में आया और बेईमानी से ही सत्ता में बना हुआ है। दूसरी तरफ भाजपा के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ पक्ष विपक्ष को अराजकतावादी कहकर यह बताना चाहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग के बहाने विपक्ष सत्ता-परिवर्तन चाह रहा है और इसके लिए वह किसी भी सीमा तक जा सकता है। हालांकि इस सीमा को परिभाषित नहीं किया जा रहा, पर यह संकेत तो मिल ही रहा है कि राजनीति के इस खतरनाक खेल में राजनेता कुछ भी कह सकते हैं, कर सकते हैं। विपक्ष की इस 'महारैली' से पहले सत्तारूढ़ पक्ष ने इस बात पर भी आपत्ति दर्ज की थी कि कांग्रेस उसी तारीख को यह आयोजन क्यों कर रही है, जब बयालीस साल पहले 1984 में राजधानी दिल्ली में सिख-विरोधी दंगे हुए थे। ज्ञातव्य है कि 31 अक्तूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद देशभर में, विशेषकर दिल्ली में, बड़े पैमाने पर सिख-विरोधी हिंसा, आगजनी और कत्लेआम हुआ था। एक से तीन नवंबर तक सिखों के विरुद्ध यह हिंसा चलती रही थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद हुए सिख-विरोधी दंगे स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक शर्मनाक काला अध्याय है। इस अध्याय को इसलिए तो याद रखना चाहिए कि फिर कभी ऐसा कांड देश में न हो, पर राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उसे याद करना देश के घावों को फिर से हरा करना ही होगा। यह कहना कि कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर एक नवंबर को यह रैली रखी, घटिया राजनीति का ही एक उदाहरण है। बहरहाल, विपक्ष का 'लोकतंत्र बचाओ' का नारा और सत्तारूढ़ पक्ष का 'अराजकता हटाओ' का नारा कुल मिलाकर एक-दूसरे के पूरक ही हैं। मतदाता सूचियों के लिए जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, वे निश्चित रूप से चिंता का विषय हैं। देश के 19 करोड़ मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित हो जाएं, यह बात किसी भी दृष्टि से उचित नहीं लगती। मतदाताओं का निधन हो जाना, स्थानांतरण कर जाना आदि तर्क गलत नहीं हैं, पर एक भी मतदाता का मतदान के अधिकार से वंचित हो जाना हमारी चुनाव-प्रणाली की कमी ही दर्शाता है। ऐसी हर कमी दूर होनी चाहिए। इस आशय की मांग को अराजकतावाद से जोड़ना उचित नहीं कहा जा सकता। और यह भी उचित नहीं है कि घुसपैठियों को भगाने के नाम पर दलगत हितों के लिए मतदाता सूची में फेर-बदल हो! घुसपैठियों, विशेषकर बांग्लादेशियों, को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, यह तो सही है, पर सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि तीन करोड़ विदेशी भारत में कैसे रह रहे हैं। हां, पहली बार देश के गृहमंत्री ने देश में तीन करोड़ घुसपैठियों के होने की बात स्वीकार की है। यह सवाल तो सरकार से पूछा ही जाना चाहिए कि इतने घुसपैठिए देश में घुसे कैसे और देश में रह कैसे रहे हैं? गृहमंत्री यह आरोप भी लगा रहे हैं कि विपक्ष इन घुसपैठियों को अपने वोट बैंक की तरह देखता है। इस आरोप की पुष्टि भी होनी चाहिए। राजधानी दिल्ली में हुई विपक्ष की 'महारैली' की सफलता-असफलता के संदर्भ में ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इनकी जांच-पड़ताल होनी ही चाहिए। लेकिन सफलता-असफलता इस आधार पर तय नहीं हो सकती कि कितने लोग रैली में एकत्र हुए अथवा कितने लाए गए या अपने आप आए। इस सबका आकलन इस बात से होना चाहिए कि जो मुद्दे इस रैली में उठे, देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनका कितना महत्व है।



आप का नजरीया

निजी क्षेत्र से वित्तीय सहयोग

वाइल्ड फ्लावर हॉल के मार्फत आ रही कमाई का हक अगर जीवंत रखा जाए तो हिमाचल की संपत्तियां अपना सदुपयोग करेंगी। जाहिर तौर पर वाइल्ड फ्लावर हॉल की कानूनी लड़ाई ने हिमाचल के स्वामित्व अधिकार लौटाते हुए नई आर्थिक भूमिका पैदा की है। ई-नीलामी के जरिए हिमाचल को वार्षिक राजस्व का 47.1 प्रतिशत हिस्सा मिल रहा है, तो अग्रिम लाइसेंस फीस के 48 करोड़ और होटल संपत्ति में 50 करोड़ का न्यूनतम निवेश भी तय हुआ है। अपनी ही मिलकीयत में कानूनी प्रतिनिधित्व की यह अनूठी मिसाल है जो प्रदेश में विनिवेश की अवधारणा को तर्कसंगत बनाएगी। सरकार ने मानदंड तय करते हुए संपत्ति के बदले चार सौ करोड़ की राशि भी प्राप्त की है। भविष्य की आर्थिक संरचना में प्रदेश को अलाभकारी संपत्तियों की घाटे में रखवाली करने के बजाय निजी क्षेत्र के साथ वित्तीय सहयोग करने के अवसर बढ़ाने होंगे। पर्यटन निगम के ही कई होटल व रेस्तरां अगर घाटे के दौर में पहुंच गए हैं, तो उन्हें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाना चाहिए। घाटे के बस डिपो, बस रूट और सार्वजनिक बोर्ड-निगमों की वित्तीय कमजोरियों को निजी क्षेत्र के सफल सहयोग के साथ बांट लेना चाहिए। वित्तीय हिफाजत या जवाबदेही के लिए यह जरूरी है कि पूरी व्यवस्था को बदला जाए। हिमाचल की कूरियर सेवाओं के साथ एचआरटीसी का गठबंधन हो जाए, तो घाटे की बसों को निजी क्षेत्र के साथ कूरिअर आमदन बांटने का अवसर मिलेगा। हिमाचल आ रही निजी वोल्वो बसों की कमाई का एक बड़ा कारण यह भी है कि प्रदेश का व्यापारी वर्ग अपना माल इनके माध्यम से ढो रहा है। सरकारी संपत्तियों का ऑडिट बता सकता है कि कितने भवन, कितने वाहन, कितने दफ्तर और कितने कर्मचारी-अधिकारी अवांछित हैं। आर्थिक संसाधन बढ़ाने से पहले फिजूलखर्ची रोकना तथा कुशल वित्तीय प्रबंधन है। सरकार अगर कुछ शिक्षण संस्थाएं या अनावश्यक संस्थान-दफ्तर बंद करती है, तो इसका मूल्यांकन सही परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। बात गुणवत्ता और काबिलीयत बढ़ाने की है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने खर्चे कम करने होंगे। प्रदेश के निजी क्षेत्र के बड़े आपरेटर, ट्रक व टैक्सी आपरेटर, सरकारी बसों से भिन्न बस या टैक्सी डिपो नहीं बनाते हैं।

अगर डीजल बसों को इलेक्ट्रिक में बदल कर सरकार करोड़ों कमा रही है, तो पांच नए इलेक्ट्रिक बस डिपो खड़े करने का खर्च अलाभकारी ही साबित होगा। हैरानी तो यह कि नगरोटा और धर्मशाला से मात्र 18-20 किलोमीटर की दूरी पर कांगड़ा में बस डिपो बनाने की घोषणा हो चुकी है। जाहिर तौर पर पूरे प्रदेश की आर्थिक, भौतिक, प्राकृतिक और व्यापारिक संपदा पर सरकार का दखल स्पष्ट है और अगर इस भूमिका में सारा अवलोकन आर्थिक धरातल पर किया जाए, तो जनता भी साथ देगी। हिमाचल की सियासी दौड़ ने आम नागरिक को सिर्फ घोषणाएं और विकास के शिलालेख ही दिए हैं, जबकि जनता को आर्थिक तरक्की का पार्टनर बनाना होगा। पंजाब राज्य के मुकाबले हिमाचल ने सबसे अधिक सरकारी कालेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल कालेज व बस डिपो खोले हैं। पर्वतीय विकास में आरंभिक गतिशीलता बेशक सरकारी ढांचे की मजबूती से ही आई, लेकिन अब जनता स्वयं निजी क्षेत्र पर भरोसा कर रही है। अच्छे स्कूल, कालेज, अस्पताल व बसों की तलाश में हिमाचल की जनता का रुझान निजी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। पिछले दस सालों से पर्यटन के डेस्टिनेशन स्थलों से निजी वोल्वो बसों का एक बड़ा बेड़ा हिमाचल में तैयार हो गया। अब यही ट्रेंड प्रदेश के विभिन्न शहरों से आगे बढ़ रहा है। चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, हरिद्वार, देहरादून व कुछ अन्य शहरों के लिए अब हिमाचल के विभिन्न भागों से वोल्वो, डीलक्स, एसी या छोटे वाहन दैनिक रूप से चल रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप सरकारी बसों के रूट असफल हो रहे हैं।

> जाहिर तौर पर वाइल्ड फ्लावर हॉल की कानूनी लड़ाई ने हिमाचल के स्वामित्व अधिकार लौटाते हुए नई आर्थिक भूमिका पैदा की है। ई-नीलामी के जरिए हिमाचल को वार्षिक राजस्व का 47.1 प्रतिशत हिस्सा मिल रहा है, तो अग्रिम लाइसेंस फीस के 48 करोड़ और होटल संपत्ति में 50 करोड़ का न्यूनतम निवेश भी तय हुआ है। अपनी ही मिलकीयत में कानूनी प्रतिनिधित्व की यह अनूठी मिसाल है जो प्रदेश में विनिवेश की अवधारणा को तर्कसंगत बनाएगी। सरकार ने मानदंड तय करते हुए संपत्ति के बदले चार सौ करोड़ की राशि भी प्राप्त की है। भविष्य की आर्थिक संरचना में प्रदेश को अलाभकारी संपत्तियों की घाटे में रखवाली करने के बजाय निजी क्षेत्र के साथ वित्तीय सहयोग करने के अवसर बढ़ाने होंगे। पर्यटन निगम के ही कई होटल व रेस्तरां अगर घाटे के दौर में पहुंच गए हैं, तो उन्हें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाना चाहिए। घाटे के बस डिपो, बस रूट और सार्वजनिक बोर्ड-निगमों की वित्तीय कमजोरियों को निजी क्षेत्र के सफल सहयोग के साथ बांट लेना चाहिए। वित्तीय हिफाजत या जवाबदेही के लिए यह जरूरी है कि पूरी व्यवस्था को बदला जाए। हिमाचल की कूरियर सेवाओं के साथ एचआरटीसी का गठबंधन हो जाए, तो घाटे की बसों को निजी क्षेत्र के साथ कूरिअर आमदन बांटने का अवसर मिलेगा। हिमाचल आ रही निजी वोल्वो बसों की कमाई का एक बड़ा कारण यह भी है कि प्रदेश का व्यापारी वर्ग अपना माल इनके माध्यम से ढो रहा है।

कुछ अलग

आइए, किताब तेरस का लाभ उठाइए

किताब प्रेमियों को यह जानकर दिमागी प्रसन्नता होगी कि इस बार किताब तेरस मनाते हम उन पर किताब वर्षा करने जा रहे हैं। ऐसी किताब वर्षा कि जिस किताब प्रेमी का मन किताब की जिल्द खरीदने तक को आज तक नहीं हुआ, वह भी किताब खरीदने को लालायित हो उठेगा, किताब पढने को मन न होने के बाद भी। किताब पढने को कराह उठेगा। अपनी अन्य कराहटों को दबाता हुआ। अबके किताब तेरस पर हमारी ओर से किताबबाजों पर जो किताब वर्षा की जा रही है, वह किसी अमृत वर्षा से कम नहीं। किताब तेरस को हम लेकर आए हैं, अपने किताबबाजों को एक से एक चमत्कारी किताबी ऑफरें। मसलन- पांच सौ रुपए तक की किताबों की फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट के साथ ऑनलाइन खरीददारी पर पिज्जा, बर्गर की तरह होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री। नो शिपिंग चार्ज। यही नहीं, इसके साथ ही साथ चुनिंदा किताबों पर अस्सी प्रतिशत तक की सीधी छूट।

दृष्टि कोण

राजनीति में क्यों आएं युवा?

आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति शांतिप्रिय, ईमानदार, सहयोगी और अपने काम से काम रखने वाला होता है। वह समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखना चाहता है। इसके विपरीत राजनीति में प्रवेश करने वाले अनेक लोग महत्वाकांक्षी हो जाते हैं और किसी न किसी तरह सत्ता एवं प्रभाव हासिल करने की कोशिश करते हैं। प्रसिद्ध नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने नाटक 'द एप्पल कार्ट' में आम जनता और राजनेताओं के संबंधों पर व्यंग्य करते हुए एक रोचक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार आम जनता पांच वर्षों के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उन्हें एक गुब्बारे में बैठाकर ऊपर भेज देती है। गुब्बारे में बैठे राजनेता पांच वर्षों तक जनता से दूर रहते हैं, जबकि जनता उनसे किए गए वादों को पूरा होने की उम्मीद में आसमान की ओर देखती रहती है। इस दौरान आम आदमी की जेब खाली होती जाती है। पांच साल बाद गुब्बारा वापस आता है और फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। परिणामस्वरूप आम आदमी और गरीब होता जाता है, जबकि राजनेता अधिक समृद्ध होते जाते हैं। इस प्रकार राजनीति कई बार आम जनता के शोषण का माध्यम बनती दिखाई देती है। इसे युवा ही रोक सकते हैं। महात्मा गांधी ने भी राजनीति के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा था, 'जो व्यक्ति यह कहता है कि उसे राजनीति में कोई रुचि नहीं है, वह उस डूबते हुए व्यक्ति के समान है जो कहता है कि उसे पानी में कोई रुचि नहीं है।' इस विषय पर आगे बढने से पहले यह समझना आवश्यक है कि राजनीति का वास्तविक अर्थ क्या है। दुर्भाग्यवश, अधिकांश लोगों



के मन में राजनीति को लेकर नकारात्मक धारणा बनी हुई है। वे इसे भ्रष्टाचार, अनैतिकता और अनुचित हथकंडों का खेल मानते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि राजनीति का संबंध किसी देश या क्षेत्र के शासन, प्रशासन और नीतियों के निर्माण से है। पुराने घाघ नेताओं की मौजूदगी के चलते भारतीय राजनीति में प्रवेश करना किसी युवा के लिए अब आसान नहीं है। इसके लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना और जनता के बीच अच्छी पहचान तथा समर्थन होना बहुत जरूरी है। एक आम आदमी जो बड़ी मुश्किल से अप

राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने की इतनी इच्छा है तो बांग्लादेश जाकर आजमाएं किस्मत : हिमंत विश्व शर्मा



पूर्णिया (हिंस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने रविवार को पूर्णिया में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। भारतीय जनता पार्टी की प्रमंडल स्तरीय *लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ* पदयात्रा से पहले रजनी चौक पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बिहार, दिल्ली, असम और उत्तर प्रदेश में चुनावी सफलता नहीं मिल रही है। शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि यदि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने की इतनी ही इच्छा है तो उन्हें बांग्लादेश जाकर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में राहुल गांधी को पैराशूट से बांग्लादेश में उतारने की बात भी कही। वोट चोरी के आरोपों पर कांग्रेस को घेरते हुए असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इसी चुनावी व्यवस्था के तहत जीतकर संसद पहुंचे हैं। यदि विपक्ष को चुनाव प्रक्रिया में बेईमानी का संदेह है तो उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के 100 अंतर्राष्ट्रीय शतकों का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी की चुनावी पराजयों पर भी कटाक्ष किया। साथ ही उन्हें अयोध्या जाकर भगवान श्रीराम के दर्शन करने की सलाह दी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का समर्थन करते हुए शर्मा ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटाने की वकालत की। उन्होंने अकबर और बाबर का उल्लेख करते हुए भारत विरोधी मानसिकता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत को नहीं मानते, उन्हें यहां की चुनावी व्यवस्था का लाभ क्यों मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने मृत मतदाताओं, दोहरी प्रविष्टियों और अपात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाने का समर्थन किया। जनसभा के बाद हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में रजनी चौक से विशाल पदयात्रा निकाली गई। यह यात्रा लखन चौक, झंडा चौक और कालीबाड़ी चौक होते हुए आरएन साव चौक पहुंचकर समाप्त हुई। इसमें पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज से आए हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल, रत्नेश सदा, विधायक विजय खेमका, कृष्ण कुमार ऋषि और कलाधर मंडल समेत कई नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।

जयपुर में भाजपा की पदयात्रा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम भजनलाल होंगे शामिल

जयपुर (हिंस)। भाजपा की ओर से *लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ* अभियान के तहत गुरुवार को जयपुर में पदयात्रा निकाली जाएगी। इसमें केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी एवं सांसद संजय भाटिया सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं अभियान के प्रदेश संयोजक रामलाल शर्मा ने बताया कि पदयात्रा सुबह 11 बजे रामलीला मैदान से शुरू होगी। यह चौड़ा रास्ता होते हुए त्रिपोलिया गेट पहुंचेगी। इसमें भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता भाग लेंगे। शर्मा ने आरोप लगाया कि विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि अभियान के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और अराजकता के विरुद्ध जनजागरण का संदेश दिया जाएगा। पदयात्रा में संगठन महामंत्री अजेय कुमार और जयपुर सांसद मंजू शर्मा सहित अन्य नेता भी शामिल होंगे।

84 के जख्म और *चिट्ठे का दर्द* पंजाब के दो गहरे दाग : रविशंकर प्रसाद



चंडीगढ़ (हिंस)। वर्ष 1984 के सिख नरसंहार के पीड़ित परिवारों और जीवित बचे लोगों की मौजूदगी में बुधवार को चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पंजाब इकाई के सम्मेलन *जख्म 84 के* का शुभारंभ हुआ। इस दौरान माहौल भावुक और गमगीन रहा। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों की आत्मिक शांति और न्याय की लड़ाई की सफलता के लिए अरदास के साथ हुई। विचार-विमर्श सत्र से पहले नवंबर 1984 की दर्दनाक घटनाओं को दर्शाती ऐतिहासिक तस्वीरों की प्रदर्शनी का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और प्रदेश प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया ने किया। प्रदर्शनी में त्रिलोकपुरी के जलते घरों, कनॉट प्लेस में आग के हवाले किए गए प्रतिष्ठानों, बेघर हुए परिवारों और बसों से सिखों को जबरन बाहर निकाले जाने की घटनाओं को तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया गया। इन तस्वीरों ने उस भयावह दौर की यादें ताजा कर दीं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज पंजाब की आत्मा पर दो गहरे दाग हैं- *84 के जख्म* और *चिट्ठे का दर्द*। इन जख्मों पर तब तक मरहम नहीं लग सकता, जब तक बिना किसी समझौते के न्याय नहीं मिलता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए रविशंकर प्रसाद ने पंजाब में उनके राजनीतिक कार्यक्रमों के समय और मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक नवंबर को कांग्रेस ने दिल्ली में रैली की और आज पंजाब में राजनीतिक कार्यक्रम कर रही है। ऐसे समय में इन ताजा जख्मों पर नमक छिड़कने की क्या जरूरत है? रविशंकर प्रसाद ने 19 नवंबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस विवादित बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था, *जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है।* प्रसाद ने आरोप लगाया कि यह बयान हजारों निर्दोष सिखों के नरसंहार को जायज ठहराने की कोशिश थी। भाजपा सांसद ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहते हुए उन्होंने उस बयान का वीडियो दोबारा सार्वजनिक अभिलेखागार में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया था, जो सार्वजनिक रिकॉर्ड से गायब हो गया था। राहुल गांधी से सवाल करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपके पिता के उस बयान पर आपका क्या रुख है?

जनता कांग्रेस और इंडी गठबंधन के झूठे नैरेटिव में आने वाली नहीं : नित्यानंद राय



पटना (हिंस)। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को सहरसा में कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर तीखा हमला बोला। *लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ* पदयात्रा अभियान के तहत सहरसा पहुंचे राय ने कहा कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेता चाहे जितना भ्रम और अफवाह फैलाने की कोशिश कर लें, देश की जनता उनके दोहरे चरित्र, नकारात्मक राजनीति और मंशा को समझ चुकी है। जनता अब उनके झूठे नैरेटिव में आने वाली नहीं है। लोगों का अटूट विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी विकासोन्मुखी नीतियों पर है। रेनबो रिसोर्ट जिला परिषद से शहीद चौक तक आयोजित पदयात्रा में उमड़ी भीड़ और लोगों के उत्साह का जिक्र करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि आज गांव-गांव, शहर-शहर और देश के हर कोने से एक ही आवाज सुनाई दे रही है- *मोदी, हम तुम्हारे साथ हैं*। यह आवाज प्रधानमंत्री के प्रति जनता के विश्वास और समर्थन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों के अन्य नेता लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर भ्रम फैलाकर देश को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके इरादों को समझ रही है। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन की पहचान भ्रष्टाचार, कुशासन, नीतिगत पंगुता और आतंकवाद के प्रति कमजोर रवैए से रही है। उस दौर में देश की सुरक्षा, युवाओं के भविष्य और विकास की आकांक्षाओं के साथ समझौता किया गया। उन्होंने कहा कि आज वही कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जनता को गुमराह करने के लिए झूठ और भ्रम का सहारा ले रहे हैं। नित्यानंद राय ने कहा कि वर्ष 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में देश की जनता ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया है। जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, सुशासन, गरीब कल्याण और विकास की राजनीति पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हुई है।

नगर निगम अजमेर आयुक्त की तानाशाही पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा

अजमेर (हिंस)। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस लीगल टीम के हेड पूर्व लोक अभियोजक अधिवक्ता विवेक पाराशर की ओर से नगर निगम अजमेर के आयुक्त गौरव बुढानिया को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत एक विधिक नोटिस प्रेषित किया गया है। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में विवेक पराशर लगभग 50 वकीलों की टीम के साथ नगर निगम पहुंचे कांग्रेस जनों ने आयुक्त के समक्ष बैठकर नियम-कानून के प्रावधानों को विस्तार से पढ़कर सुनाया तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के विभिन्न महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धांतों एवं आदेशों की प्रतियां भी उन्हें सौंपी।

पंजाब में कर्मचारियों व पेंशनरों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ा



चंडीगढ़ (हिंस)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए दिवाली के तोहफे के रूप में महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का एलान किया, जिससे हमारी सरकार के कार्यकाल में महंगाई भत्ता 2022 के 28 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिसंबर के वेतनों और पेंशनों के साथ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से पंजाब के आठ लाख कर्मचारियों व पेंशन भोगियों को लाभ होगा। इस एलान से पिछले दो महीनों में महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिससे आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारें अक्सर खजाना खाली होने का रोना रोती थी, लेकिन हमारी सरकार ने कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता दी और यह सुनिश्चित किया कि कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके जायज हक से वंचित रखने में वित्तीय मुश्किलों को बहाना नहीं बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज पंजाब के लगभग आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली के तोहफे के रूप में हमने महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का एलान किया है। इससे डीए बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है, जिससे कर्मचारियों को लगभग 3,988 करोड़ रुपए का सालाना वित्तीय लाभ मिलेगा। कर्मचारी हमारी सरकार की रीढ़ की हड्डी हैं और हम उनकी भलाई, हक और सर्वांगीण कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को दिवाली की लाख-लाख बधाई। इस बीच पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबे के प्रशासन और लोक सेवा में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के अतुलनीय योगदान को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी और पेंशनर पंजाब सरकार के पारिवारिक सदस्य हैं और प्रशासनिक मशीनरी की रीढ़ की हड्डी हैं। वे आम लोगों की शिकायतों को दूर करने, अमन-कानून बनाए रखने और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए पूरी तनदेही और समर्पण भावना से अपनी ड्यूटियां निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बिना किसी रिश्वत या सिफारिश के पूरी तरह मेरिट के आधार पर नौजवानों को 71,777 सरकारी नौकरियां दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बढ़ोतरी पहली नवंबर से लागू होगी और दिसंबर महीने में दी जाने वाली तनख्वाह और पेंशन में तीन की बढ़ोतरी शामिल होगी। इस बढ़ोतरी से पंजाब में डीए 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है। जब हमने 2022 में पदभार संभाला था तो सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ 28 प्रतिशत की दर से डीए मिल रहा था। महज दो महीने पहले सितंबर में डीए में आठ प्रतिशत बढ़ोतरी का एलान किया गया था। यह पहली बार है, जब किसी सरकार ने महज दो महीनों के अंतराल में डीए में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि इस 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी से मौजूदा वित्तीय साल के दौरान कर्मचारियों और पेंशनरों को 1,813 करोड़ रुपए का फायदा होगा।

गोरखपुर : योगी आदित्यनाथ ने सपा -कांग्रेस पर जमकर किए प्रहार

बोले, राहुल गांधी फुस्स रॉकेट, लांच नहीं होने वाले



गोरखपुर (हिंस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस, सपा सहित पूरा इंडी गठबंधन भारत की विकास व आत्मनिर्भरता की यात्रा में लगातार रोड़े अटका रहा है। कांग्रेस और उसका इंडी गठबंधन दिल्ली में अराजकता पैदा कर लोकतंत्र के लिए खतरा बना हुआ है। राहुल गांधी फुस्स रॉकेट हैं, जिनका बारूद खत्म हो चुका है, सिर्फ धुआं बचा है। कांग्रेस चाहे जितनी बार उन्हें लांच कर ले, अब वह लांच नहीं होने वाले। मुख्यमंत्री योगी बुधवार को गोरखपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में निकाली गई *लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ* पदयात्रा शुरू करने से पहले महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने नबीन का बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षधरा में प्रथम आगमन पर भावपूर्ण स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस, सपा और इंडी गठबंधन के दल अगर चुनाव जीतते हैं तो परिणाम उनका पुरुषार्थ होता है। और यदि जनता उनके नकारेपन के कारण जवाब दे देती है, वे हार जाते हैं तो ईवीएम पर दोष थोपना उनकी प्रवृत्ति बन गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सभी सहयोगियों को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। वंबर को कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया। यह सिखों पर अत्याचार को याद दिलाने वाली तारीख थी। 01 नवंबर 1984 को दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेसियों द्वारा निर्दोष सिखों को कत्लेआम किया जा रहा था। तब भारत के अंदर हिंदू और सिख भाई-भाई के रूप में रह रहे थे, लेकिन कांग्रेस के कृत्यों के कारण इसमें किसी न किसी प्रकार से खाई पैदा हुई। देश के अंदर माहौल खराब करने का कार्य कांग्रेस ने किया था। जब देश उन निर्दोष सिखों के कत्लेआम की बरसी मना रहा था, उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा था, तब कांग्रेस के लोग दिल्ली के अंदर जश्न मना कर उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की राजनीतिक लॉन्चिंग पर तंज कसते हुए कहा कि दीपावली पर कुछ रॉकेट ऐसे होते हैं, जिन्हें जलाने के बाद लोग आसमान की ओर देखते रह जाते हैं, लेकिन रॉकेट वहीं धुआं छोड़कर बुझ जाता है। राहुल गांधी की भी यही स्थिति हो चुकी है। कांग्रेस ने वर्ष 2004 में सांसद, 2007 में महासचिव, 2013 में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 2017 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर राहुल गांधी को लांच किया। इसके बाद 2019 में वह अमेठी से चुनाव हार गए। भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा और अधिकार यात्रा से भी स्थिति नहीं बदली। राहुल गांधी 56 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए अब भी युवा हैं। अब यह युवा कभी लांच नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में 44, वर्ष 2019 में 52 और वर्ष 2024 में 99 सीटें मिलीं। तीनों चुनावों में कुल 195 सीटें मिलीं, जबकि भाजपा ने अकेले 2024 में 240 सीटें जीतीं। उन्होंने बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों का उल्लेख करते हुए कहा कि बार-बार की हार के बावजूद कांग्रेस आत्ममंथन नहीं करती। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। कुछ लोग देश को बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका जैसा बनाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन नया भारत अराजकता स्वीकार नहीं करेगा। वर्ष 2017 से पहले सपा की चार सरकारों में 1500 से अधिक दंगे हुए। पर्व-त्योहारों से पहले कर्फ्यू लगना आम था। बेटियां और व्यापारी असुरक्षित थे। आज प्रदेश सुरक्षा और सुशासन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाजपा की पदयात्रा केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। पदयात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन अराजकता फैलाकर आमजन को गुमराह कर रहा है। एक तरफ विपक्ष अराजकता फैला रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरा है। पहले भारत कुछ कहता था तो दुनिया सुनती नहीं थी, लेकिन आज भारत कुछ कहता है तो दुनिया सुनती भी है और अमल भी करती है। केंद्रीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास कमलेश पासवान, प्रदेश सरकार के

राजस्थान में जीएसटी लागू होने के बाद अक्तूबर में जुटाए 7,047 करोड़ रुपए

जयपुर (हिंस)। राजस्थान ने कर राजस्व संग्रहण के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जीएसटी लागू होने के बाद अक्तूबर 2026 में प्रदेश ने अब तक का सर्वाधिक मासिक जीएसटी एवं मूल्य वर्धित कर (वैट) राजस्व संग्रहण दर्ज किया। इस दौरान राज्य को कुल 7,047.27 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और प्रमुख शासन सचिव (कर) की नियमित निगरानी को इस उपलब्धि का प्रमुख आधार बताया गया है। कर विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अक्तूबर 2026 का संग्रहण मार्च 2026 में दर्ज 6,826.60 करोड़ रुपए के पिछले रिकॉर्ड से 220.67 करोड़ रुपए अधिक रहा। इस प्रकार विभाग ने अपने ही पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। एक ही महीने में इतने बड़े स्तर पर राजस्व संग्रहण को राज्य के कर प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अक्तूबर 2025 में राजस्थान को जीएसटी और वैट से 6,303.88 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। इसके मुकाबले अक्तूबर 2026 में संग्रहण बढ़कर 7,047.27 करोड़ रुपए पहुंच गया। इस तरह एक साल में राजस्व संग्रहण में 743.39 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई, जो लगभग 11.79 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अप्रैल से अक्तूबर तक प्रदेश का कुल जीएसटी एवं वैट राजस्व संग्रहण 44,034.09 करोड़ रुपए रहा। सरकार के अनुसार, कर अनुपालन में सुधार, राजस्व संग्रहण की नियमित समीक्षा, अधिकारियों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने और कर चोरी पर अंकुश लगाने के प्रयासों से विभागीय कार्यप्रणाली को मजबूती मिली है। राज्य सरकार करदाताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ कर प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर भी जोर दे रही है। प्रमुख शासन सचिव स्तर पर राजस्व संग्रहण की नियमित समीक्षा और अधिकारियों के कामकाज की निगरानी की जा रही है।

ट्रक की टक्कर से तीन दोस्तों की मौत, बाइक के उड़े परखच्चे

सिरोही (हिंस)। राजस्थान के सिरोही जिले में नेशनल हाईवे-27 पर मंगलवार रात एक सड़क हादसे में तीन दोस्तों की जान चली गई। आबूरोड थाना क्षेत्र के मावल कट के पास तेज रफ्तार ट्रक ने आगे चल रही बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और तीनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में तीनों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसा मंगलवार रात करीब 10:30 बजे हुआ। आबूरोड से गुजरात के पालनपुर की ओर जा रहे ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों युवकों को एंबुलेंस की सहायता से सरकारी उपजिला अस्पताल आबूरोड पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान प्रकाश और शंकर निवासी देलवाड़ा माउंट आबू तथा दिनेश उर्फ विनय निवासी चारनिया फली सातपुर आबूरोड के रूप में हुई है। प्रकाश और शंकर पड़ोसी थे, जबकि दिनेश उनका दोस्त था। तीनों युवक मजदूरी करके अपना जीवनयापन करते थे और अविवाहित थे। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिवारों में शोक छा गया। प्रकाश के भाई प्रवीण ने बताया कि प्रकाश बिना बताए घर से निकला था। रात करीब 12 बजे परिवार को सड़क दुर्घटना में उसकी मौत होने की सूचना मिली। प्रकाश के माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका था। उसके तीन भाई और चार बहनें हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। वहीं, दिनेश के पिता का निधन हो चुका था। परिवार में उसकी मां और दो बहनें हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। शंकर के परिवार में एक भाई और तीन बहनें हैं। उसकी मां का भी निधन हो चुका था, जबकि पिता मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करते हैं। तीनों युवकों की असमय मौत से उनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आबूरोड थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह के अनुसार पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है।

हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की दो दिवसीय हड़ताल स्थगित

चंडीगढ़ (हिंस)। हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों ने पांच नवंबर से प्रस्तावित दो दिवसीय हड़ताल स्थगित कर दी है। बुधवार को परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और रोडवेज कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच करीब चार घंटे तक चली बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। अधिकारियों ने कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा के लिए 25 नवंबर को परिवहन मंत्री अनिल विज के साथ बैठक कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद कर्मचारी हड़ताल टालने पर सहमत हो गए। दरअसल, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गुरुवार को हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह करनाल और अंबाला में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ऐसे में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल का एलान सरकार के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। बुधवार को हुई बैठक में रोडवेज की 12 यूनियनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। संयुक्त मोर्चा के अनुसार, कर्मचारियों की आठ प्रमुख मांगों पर चर्चा के लिए 25 नवंबर को परिवहन मंत्री अनिल विज के साथ दोबारा बैठक होगी। फिलहाल त्योहारी सीजन और आम जनता की परेशानी को देखते हुए हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। रोडवेज कर्मचारी वर्ष 2016 की भर्ती के तहत नियुक्त कर्मियों को नियमित करने और पिछले 10 वर्षों का दिवाली बोनस देने समेत अन्य मांगें उठा रहे हैं। बैठक में शामिल हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के जगबीर घनघस, नीरज शर्मा और माया राम ने बताया कि कई मांगों पर चर्चा के दौरान सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि जनता के हितों और त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए दो दिवसीय हड़ताल नहीं करने का फैसला लिया गया है। अब परिवहन मंत्री के साथ 25 नवंबर को होने वाली बैठक के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी।

लोकतंत्र जनादेश के सम्मान से सशक्त होता है, अराजकता से नहीं : केशव प्रसाद मौर्य

प्रयागराज (हिंस)। लोकतंत्र जनता के जनादेश के सम्मान से मजबूत होता है, अराजकता और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाने से नहीं। विपक्षी दलों को चुनाव में हार के बाद वोट चोरी का आरोप लगाने के बजाय अपने राजनीतिक आचरण पर नजर डालनी चाहिए। यह बातें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को भाजपा की ओर से निकाली गई *लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ* पदयात्रा के दौरान कहीं। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष तख्तापलट की बात करता है, लेकिन जनता ऐसा नहीं होने देगी। जनता ही उनका तख्तापलट कर देगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन को जनादेश पर सवाल उठाने तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास फैलाने के बजाय लोकतंत्र की मर्यादा का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रयागराज की इस ऐतिहासिक पदयात्रा को राहुल गांधी वियतनाम से, सोनिया गांधी दिल्ली से और अखिलेश यादव सैफई से देख रहे होंगे। उन्होंने कांग्रेस पर वोट चोरी और समाजवादी पार्टी पर बूथ कब्जे की राजनीति करने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं से 2027 के विधानसभा चुनाव में हर बूथ पर कमल खिलाने के संकल्प के साथ जुटने का आह्वान किया। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का उल्लेख करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने 13 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि सर्वे के दौरान अनुपस्थित पाए गए मतदाताओं, मृत घोषित लोगों और एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज होने वाले दोहरे मतदाताओं के कारण नाम हटाए गए हैं। उनके अनुसार, इस प्रक्रिया में अनुपस्थित मतदाताओं का हिस्सा 23 प्रतिशत, मृत घोषित लोगों का 21 प्रतिशत से अधिक और दोहरे मतदाताओं का 7.6 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को दुरुस्त करना लोकतंत्र और संविधान के हित में है। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और चुनाव आयोग तथा सर्वोच्च न्यायालय ने दुनिया में अपनी विश्वसनीयता स्थापित की है। विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया है और उनके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है। घुसपैठियों को देश की व्यवस्था और मतदाता सूची का हिस्सा बनने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कार्यकर्ताओं से विपक्ष के दुष्प्रचार का जवाब देने और संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की अपील की। सपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अब उसकी साइकिल पंचर करने का समय आ गया है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि जब कुछ विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते तो अपनी कमी स्वीकार करने के बजाय शिक्षक को गलत ठहराने लगते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी चुनाव में हार के बाद ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। उन्हें व्यवस्था को दोष देने के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2027 के विधानसभा चुनाव में हर बूथ पर कमल खिलाने के लिए जुटने का आह्वान किया। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी को आपातकाल का दौर याद करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी दादी इंदिरा गांधी के कार्यकाल को याद करना चाहिए, जब आपातकाल के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को जेल में डाल दिया गया था। लोकतंत्र और संविधान की बात करने से पहले कांग्रेस को अपने इतिहास पर नजर डालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने ही मतपत्र से लेकर ईवीएम तक की चुनाव व्यवस्था अपनाई थी, लेकिन अब चुनाव हारने पर उसी व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भाजपा की ओर से निकाली गई पदयात्रा में प्रयागराज महानगर, गंगापार, यमुनापार के साथ काशी, भदोही, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और सुल्तानपुर सहित काशी क्षेत्र के विभिन्न जनपदों से हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। पदयात्रा धरना स्थल से शहीद वॉल तक निकाली गई। एक रथ पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, अनिल राजभर, राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा और सुरेंद्र चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि एवं पार्टी पदाधिकारी सवार थे। आगे चल रह



धनतेरस के पहले सर्राफा बाजार में चमका सोना, चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं

नई दिल्ली

घरेलू सर्राफा बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान सोने की कीमत में तेजी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। भाव में उछाल आने के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में सोना 250 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 270 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। माना जा रहा है कि सोने के भाव में धनतेरस और दिवाली की वजह से तेजी का ये माहौल बना है। दूसरी ओर चांदी के भाव में लगातार दूसरे दिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। शुरुआती कारोबार में भी ये चमकीली धातु सोमवार के भाव पर ही बिक रही है।

भाव में बदलाव आने के कारण देश के अलग-अलग सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,39,650 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,39,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना 1,28,010 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,28,160 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। दूसरी ओर, चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं होने के कारण यह चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में भी 1,99,900 रुपये प्रति किलोग्राम के पुराने स्तर पर ही बिक रही है।

दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,39,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,28,160 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,39,650 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,28,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,39,700 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,28,060 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,39,650 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,28,010 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,39,650 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,28,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,39,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,28,060 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,39,800 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,28,160 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,39,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,28,060 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

चंडीगढ़ में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,39,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,28,160 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,39,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,28,160 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी सोना मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

न्यूज ब्रीफ

अनिश्चितता के दौर में लार्जकैप पर बढ़ा भरोसा, विशेषज्ञ बोले, अगले 6-18 महीने बेहतर रिटर्न की उम्मीद



नई दिल्ली। साल 2026 में शेयर बाजार का रुख बदल गया है। अब तक बाजार की तेजी में आगे रहे मिडकैप और स्मालकैप शेयरों की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जबकि अनिश्चितता के बीच निवेशक सुरक्षित ठिकाने के रूप में लार्जकैप शेयरों की ओर रुख कर रहे हैं। 11 सितंबर के बाद यह रुझान स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। आंकड़ों के अनुसार, 11 सितंबर से 2 नवंबर के बीच निफ्टी 50 में जहां 0.5 फीसदी की मामूली गिरावट आई, वहीं निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 7 फीसदी और निफ्टी स्मालकैप 100 इंडेक्स 6.6 फीसदी लुढ़क गया। यह बदलाव दर्शाता है कि निवेशक अब मजबूत कारोबार, आसान तरलता और स्थिर कमाई वाली बड़ी कंपनियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 6 से 18 महीनों में लार्जकैप शेयर जोखिम के मुकाबले बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। अमेरिका चुनाव, कंपनियों की कमाई और वैश्विक तनाव जैसी कई अनिश्चितताएं बाजार के सामने हैं। ऐसे माहौल में लार्जकैप शेयर निवेशकों को अधिक स्थिरता दे रहे हैं। मजबूत कारोबार, बैलेंस शीट और स्थिर कमाई वाली बड़ी कंपनियां आकर्षक बनी हुई हैं। एफआईआई की लगातार बिकवाली चुनौती रही है, पर वैश्विक भरोसा बढ़ने पर निफ्टी 50 कंपनियां, प्राइवेट बैंक और वित्तीय सेवा प्रदाता सबसे पहले लाभ उठा सकते हैं।

घर बैठे मनाएं, जेप्टो और ब्लिंकिट पर मिलेगा सारा सामान



नई दिल्ली। आस्था और लोकपर्व छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जो 15 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दौरान बाजारों में लगने वाली भारी भीड़ और खरीदारी की जद्दोजहद से बचने के लिए, जेप्टो और ब्लिंकिट जैसे आनलाइन क्विक कामर्स प्लेटफार्म श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी राहत लेकर आए हैं। अब आप घर बैठे ही छठ पूजा से जुड़ा लगभग सभी आवश्यक सामान आसानी से मंगवा सकते हैं। इन प्लेटफार्म्स पर कपूर, देसी घी के दीये, रुई की बाती, अगरबत्ती, धूप, रोली, मौली और चावल जैसी पारंपरिक पूजा सामग्री आसानी से मिल रही है। इसके साथ ही, पूजा की थाली, लाल-पीले वस्त्र और ठेकुआ बनाने के लिए आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध है। व्रतियों के लिए विभिन्न प्रकार के ताजे फल जैसे केला, सेब, अमरूद और अनार भी घर बैठे मंगाए जा सकते हैं। इन क्विक कामर्स सेवाओं का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपका सामान अक्सर मिनटों के भीतर ही घर तक पहुंच जाता है, जिससे समय की बचत होती है और बाजार जाने की परेशानी खत्म हो जाती है। आनलाइन खरीदारी के इच्छुक लोग जेप्टो और ब्लिंकिट ऐप में पूजा, नीड्स, फेस्टिव या स्पेशल जैसे सेक्शन में जाकर अपनी आवश्यकतानुसार सामान ढूंढ सकते हैं।

एक्सिस एमएफ फ्रंट रनिंगः सेबी ने 4 इकाइयों पर 40 लाख का जुर्माना लगाया



नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने एक्सिस म्यूचुअल फंड के कारोबार में कथित फ्रंट-रनिंग को बढ़ावा देने के मामले में दो शेयर ब्रोकिंग फर्मों और उनके दो निदेशकों समेत चार इकाइयों पर कुल 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वुडस्टाक ब्रोकिंग और उसके डायरेक्टर सुरेश कनमल जाजू, साथ ही मारफतिया स्टाक ब्रोकिंग और उसके डायरेक्टर निशिल सुरेंद्र मारफतिया पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई सेबी की 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की जांच के बाद की गई। जांच में पाया गया कि इन ब्रोकरों ने दुबई में बैठे प्रिजेश कुरानी नामक एक अनधिकृत व्यक्ति को अपने ओडिन ट्रेडिंग टर्मिनल इंस्टाल और संचालित करने में मदद की। कुरानी ने एक्सिस म्यूचुअल फंड के बड़े सौदों से पहले अपने सौदे कर फ्रंट रनिंग को अंजाम दिया। सेबी ने वुडस्टाक ब्रोकिंग के खिलाफ व्हाट्सएप चैट, आईपी एड्रेस और मैक आईडी जैसे तकनीकी साक्ष्यों के साथ-साथ एनीडेस्क के माध्यम से रिमोट एक्सेस को आधार बनाया। वहीं, मारफतिया स्टाक ब्रोकिंग के मामले में उसके मैनेजिंग डायरेक्टर के बयान और आईटी कर्मचारियों के साथ हुई व्हाट्सएप बातचीत को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया गया।

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत एशिया में बिकवाली का दबाव

नई दिल्ली

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान बढ़त के साथ बंद हुए थे। वहीं डाउ जोन्स फ्यूचर्स सुबह गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान कमजोरी का माहौल बना रहा, जहां प्रमुख सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं एशियाई बाजार से कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं, हालांकि भारतीय बाजार के लिए शुरुआती संकेत बेहतर नजर आ रहे हैं।



अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र में मजबूती का रुख देखने को मिला। एसएंडपी 500 इंडेक्स 27.85 अंक यानी 0.37 प्रतिशत की बढ़त के साथ 7,569.25 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं टेक कंपनियों से जुड़े नैस्डैक कंपोजिट ने भी 207.69 अंक यानी 0.83 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,372.01 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके विपरीत, सुबह डाउ जोन्स फ्यूचर्स फिलहाल दबाव में नजर आ रहा है। यह सूचकांक 405.65 अंक यानी 0.78 प्रतिशत टूट कर 51,381.07 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

अमेरिकी बाजार के विपरीत यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान बिकवाल हावी रहे। ब्रिटेन का एफटीएसई इंडेक्स 122.90 अंक यानी 1.16 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज करते हुए 10,638.43 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह जर्मनी के डीएएक्स इंडेक्स ने 116.47 अंक यानी 0.45 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,864.62 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। वहीं फ्रांस का सीएसी इंडेक्स 27.38 अंक यानी 0.34 प्रतिशत की सुस्ती के साथ 8,020.31 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

ग्लोबल मार्केट के इन संकेतों के बीच एशियाई बाजार में सुबह भारी बिकवाली का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। एशिया के नौ प्रमुख बाजार में से सिर्फ एक सूचकांक बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि आठ सूचकांक बिकवाली के भारी दबाव में लाल निशान में बने हुए हैं। राहत की बात यह है कि भारतीय बाजार के लिए शुरुआती संकेत देने वाले गिफ्ट निफ्टी में सुबह तेज उछाल का रुख बना हुआ है, जो घरेलू बाजार के लिए बेहतरीन संकेत हैं। फिलहाल यह सूचकांक 204.50 अंक यानी 0.86 प्रतिशत की जोरदार मजबूती के साथ 23,964.50 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

दूसरी ओर, जापान का निक्केई 225 इंडेक्स भारी कमजोरी के साथ लाल निशान में पहुंचा हुआ है। फिलहाल यह सूचकांक 2,701.86 अंक यानी 4.28 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 60,380 अंक के स्तर पर बना हुआ है। दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में भी बड़ी मंदी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। चौतरफा बिकवाली के दबाव से फिलहाल यह सूचकांक 192.80 अंक यानी 3.41 प्रतिशत की बड़ी गिरावट के साथ 5,455.99 अंक के स्तर पर आ गया है।

इसी तरह ताइवान स्टाक एक्सचेंज में भी जबरदस्त कमजोरी का माहौल बना हुआ है। लगातार हो रही मुनाफावसूली के कारण ताइवान वेटेड इंडेक्स 1,226.70 अंक यानी 2.83 प्रतिशत फिसल कर 42,080.84 अंक के स्तर पर आ गया है। थाईलैंड के सेट कंपोजिट इंडेक्स में भी सुस्ती नजर आ रही है। यह सूचकांक फिलहाल 13.31 अंक यानी 0.89 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,477.70 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इंडोनेशिया स्टाक एक्सचेंज में भी बिकवाल हावी नजर आ रहे हैं, जिसके कारण जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स 26.47 अंक यानी 0.54 प्रतिशत की मंदी के साथ 4,877.82 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। हान्गकान्ग के शेयर बाजार में भी मामूली गिरावट का रुख बना हुआ है, जहां हैंगसेंग इंडेक्स फिलहाल 32.97 अंक यानी 0.14 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 23,493 अंक के स्तर पर आ गया है। इसी तरह चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स भी लाल निशान में फिसल गया है। फिलहाल यह सूचकांक 3.73 अंक यानी 0.10 प्रतिशत की मामूली कमजोरी के साथ 3,604.37 अंक के स्तर पर बना हुआ है। इसके अलावा सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स भी दबाव में काम करता नजर आ रहा है। फिलहाल यह सूचकांक 3.90 अंक यानी 0.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 5,200.07 अंक के स्तर पर बना हुआ है।

आरबीआई ने सेवा निर्यात-आयात के नियमों में ढील दी, फ्रीलांसरों को राहत



नई दिल्ली

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सर्विस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जुड़े विदेशी मुद्रा नियमों में महत्वपूर्ण ढील दी है, जिससे विदेशी क्लाइंट्स से कमाई करने वाले फ्रीलांसरों, कंपनियों और आयातकों को बड़ी राहत मिली है। इन बदलावों का उद्देश्य छोटे ट्रांजेक्शन और सेवा भुगतानों की प्रक्रिया को सरल बनाना है, जिससे कागजी कार्रवाई और लगने वाले समय में कमी आएगी।

नए नियमों के तहत भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को अब विदेश में सेवा देने के बदले भुगतान मिलने पर अलग से एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फार्म (ईडीएफ) जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल अपने बैंक को भुगतान खाते में जमा करने के लिए आवश्यक जानकारी देनी होगी।

यह कदम विशेष रूप से डिजिटल सेवाओं और फ्रीलांसिंग के बढ़ते क्षेत्र को बढ़ावा देगा, जहां अक्सर छोटे भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त होते हैं। जो निर्यातक भारत में रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं, उन्हें भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। ऐसे निर्यातकों के लिए विदेश से आने वाली सर्विस पेमेंट 10 लाख रुपये तक होने पर सिर्फ बैंक को जरूरी जानकारी देनी होगी; इससे अधिक राशि पर पहले के डिक्लेरेशन की शर्तें ही लागू होंगी। आरबीआई ने सर्विस इंपोर्ट के मामले में भी रिपोर्टिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब बैंकों को इम्पोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मानिटरिंग सिस्टम (आईडीपीएमएस) में सर्विस इंपोर्ट की जानकारी तभी दर्ज करनी होगी, जब सेवा खरीदने वाला भारत का निवासी न हो और इनवायस 10 लाख रुपये से अधिक हो। इन बदलावों से विदेशी व्यापार से जुड़े लेन-देन की प्रक्रिया में लगने वाले समय और कागजी कार्रवाई में कमी आएगी, जिससे भारत में ईज आफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा।

छोटे ट्रांजेक्शन और डिजिटल सेवाओं के लिए ईडीएफ की बाध्यता खत्म

यूपी सरकार दिवाली पर उज्ज्वला लाभार्थियों को बांटेगी निःशुल्क गैस सिलेंडर



लखनऊ। दीपावली के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक बड़ी सौगात दी है। राज्य में निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरण प्रक्रिया का शुभारंभ हो गया है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्वच्छ ईंधन का सीधा लाभ मिलेगा। यह पहल लाखों परिवारों के लिए त्योहार को और भी रोशन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लखनऊ के लोकभवन से इस योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत, उज्ज्वला योजना के प्रत्येक लाभार्थी के खाते में कुल 971 रुपये (राज्य सरकार से 653 रुपये और केंद्र सरकार से 318 रुपये) की सब्सिडी सीधे हस्तांतरित की जा रही है। यह सुविधा लाभार्थियों को साल में दो बार प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें ईंधन के खर्च से राहत मिलेगी और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत, जनपद एटा में भी जिलाधिकारी एम अरुन्मोली की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने लाभार्थी महिलाओं को प्रतीकात्मक चेक वितरित करते हुए केंद्र व राज्य सरकार की इस पहल की सराहना की, जो स्वच्छ ईंधन सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर है।

शेयर बाजार में उतरेगी रेजर-पे, सेबी से आईपीओ लाने के लिए मिली हरी झंडी

नई दिल्ली

देश की जानी-मानी फिनटेक स्टार्टअप रेजर-पे जल्द ही प्राइमरी शेयर बाजार में दस्तक देने जा रही है। कंपनी को अपना पहला पब्लिक इश्यू (आईपीओ) लाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया (सेबी) से हरी झंडी मिल चुकी है। सूत्रों के अनुसार, कंपनी इस पब्लिक इश्यू के जरिये 5,500 करोड़ रुपये से लेकर 6,500 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाने की तैयारी में है।

रेजर-पे ने अपने पब्लिक इश्यू के लिए जून 2026 में कान्फिडेंशियल प्री-फाइलिंग रूट के तहत गोपनीय तरीके से सेबी के पास अपने दस्तावेज जमा कराए थे। कान्फिडेंशियल प्री-फाइलिंग रूट के तहत कंपनियां अपनी बेहद संवेदनशील वित्तीय जानकारियों को सार्वजनिक किए बिना ही आईपीओ की शुरुआती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती हैं।

इस आईपीओ के जरिये कंपनी का लक्ष्य करीब 500 करोड़ डालर यानी लगभग 49,000 से 50,000 करोड़ रुपये का वैल्यूएशन हासिल करना है। हालांकि, यह आंकड़ा कंपनी के पिछले मूल्यांकन से थोड़ा कम नजर आ रहा है। इसके पहले साल 2021 के एक फंडिंग राउंड के दौरान रेजर-पे को करीब 750 करोड़ डालर का वैल्यूएशन मिला था। आपको बता दें कि



आईआईटी रुड़की से पढ़ाई करने वाले हर्षिल माथुर और शशांक कुमार द्वारा साल 2014 में शुरू की गई यह कंपनी व्यापारियों को डिजिटल बैंकिंग, पेमेंट गेट-वे और पेमेंट प्रोसेसिंग जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं देती है।

रेजर-पे में टाइगर ग्लोबल, पीक एक्सवी पार्टनर्स और जीआईसी जैसे बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया हुआ है। बाजार में इस कंपनी का मुकाबला पेटीएम, पे-यू, पाइन लैब्स, कैशफ्री पेमेंट्स और फोन-पे जैसी दिग्गज कंपनियों से है। इन प्रतिद्वंद्वी कंपनियों में से पाइन लैब्स और पेटीएम पहले से ही घरेलू शेयर बाजार की लिस्टेड कंपनियां हैं। वहीं फोन-पे के भी 2026-27 के अंत तक लिस्ट होने की उम्मीद है।

यदि कंपनी की हालिया वित्तीय स्थिति पर नजर डालें, तो वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान इसका कुल राजस्व सालाना आधार पर 65 प्रतिशत की शानदार बढ़त के साथ 3,783 करोड़ रुपये पर पहुंच गया था। इस अवधि में कंपनी का ग्रास प्राफिट भी बढ़कर 1,277 करोड़ रुपये रहा। हालांकि, इसी वित्त वर्ष में कंपनी को 1,209 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा भी उठाना पड़ा है।

भारत में 2027 से विमान ईंधन में एसएएफ का उपयोग अनिवार्य होगा

नई दिल्ली

भारत सरकार हवाई यात्रा को पर्यावरणीय रूप से अधिक टिकाऊ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट एसएएफ पालिसी, 2026 के तहत विमानों के ईंधन एटीएफ(एविएशन टर्बाइन फ्यूल) में एसएएफ (सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल) का मिश्रण अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है।

इस नई नीति के लागू होने पर, जनवरी 2027 से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में कम से कम एक फीसदी का उपयोग करना होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी की ड्राफ्ट एसएएफ पालिसी, 2026

हवाई यात्रा से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित यह नीति अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए जनवरी 2027 से एक फीसदी एसएएफ के उपयोग को अनिवार्य करेगी और 2040 तक इस लक्ष्य को 20 फीसदी तक बढ़ाने का स्पष्ट रोडमैप प्रदान करती है। एसएएफ पारंपरिक विमान ईंधन का एक पर्यावरण-अनुकूल विकल्प है, जिसे फसल, जैविक कचरे और अन्य टिकाऊ स्रोतों से तैयार किया जाता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य हवाई यात्रा के कार्बन पदचिह्न को कम करना है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि एसएएफ गुणवत्ता



और सुरक्षा मानकों पर खरा उतरे। ड्राफ्ट नीति में केवल एसएएफ मिश्रण के लक्ष्य ही नहीं, बल्कि इनके सख्त अनुपालन पर भी जोर दिया गया है। निर्धारित ब्लेंडिंग जरूरत को पूरा न करने वाली एयरलाइंस और तेल मार्केटिंग कंपनियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, नीति में यह भी प्रस्तावित है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस अपनी वार्षिक एटीएफ जरूरतों का कम से कम 90 फीसदी भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से पूरा करेंगी, जिसका लक्ष्य इकोनामिक टैंकरिंग को रोकना है। हवाई अड्डों को एसएएफ के भंडारण, रखरखाव और वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि एसएएफ के उपयोग से एयरलाइंस की ईंधन लागत पर असर पड़ सकता है, खासकर यदि एसएएफ पारंपरिक एटीएफ से महंगा होता है, तो हवाई टिकटों की कीमतों में वृद्धि संभव है। हालांकि, फिलहाल हवाई टिकटों के महंगा होने की कोई तत्काल संभावना नहीं जताई गई है।

यह कदम भारत को वैश्विक स्तर पर पर्यावरण अनुकूल हवाई यात्रा को बढ़ावा देने वाले देशों की श्रेणी में खड़ा करेगा।



पंजाब किंग्स ने सीएसके से यांनसन के ट्रेड ड्रील की संभावनाओं को खारिज किया

चेन्नई

आईपीएल फ्रैंचाइजी पंजाब किंग्स ने कहा है कि वह दक्षिण अफ्रीकी आलराउंडर मार्को यानसन को लेकर चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) या किसी अन्य टीम के साथ किसी प्रकार की ट्रेड डील पर बात नहीं कर रही है। इससे पहले कहा जा रहा था कि पंजाब किंग्स यानसन को ट्रेड डील के जरिये सीएसके को दे सकती है।

वहीं अब पंजाब फ्रेंचाइजी ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल उन्हें रिलीज या ट्रेड करने का उनका कोई इरादा नहीं है, जिससे यानसन के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। यानसन के लिए आईपीएल 2026 का सत्र अच्छा नहीं रहा था। उन्होंने पंजाब किंग्स के लिए 12 मैचों में केवल 9 विकेट लिए, जहां उनका गेंदबाजी औसत 53.66 और इकानमी रेट 10.20 रहा, जो टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। वहीं बल्लेबाजी में भी वे पांच पारियों में सिर्फ 51 रन ही बना पाए जबकि 2025 की नीलामी में पंजाब ने उन्हें 7 करोड़ रुपये खर्च करके अपनी टीम में शामिल किया था पर आईपीएल में उनका प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार नहीं रहा था। ऐसे में माना जा रहा था कि पंजाब उन्हें छोड़ सकती है। वहीं आईपीएल के खराब प्रदर्शन के बावजूद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मार्को यानसन का बेहरीन प्रदर्शन जारी रहा। दक्षिण अफ्रीका के लिए उन्होंने इस साल टी20 अंतरराष्ट्रीय अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी की है। माना जा रहा है कि उनकी इसी बेहतरीन फार्म को देखते हुए पंजाब किंग्स उन्हें अपनी टीम में बनाए रखना चाहती है, जिससे वे आगामी सीज़न में अपनी आलराउंड क्षमता का पूरा प्रदर्शन कर सकें और टीम को मजबूती प्रदान कर सकें। वहीं दूसरी ओर सीएसके का प्रदर्शन पिछले सत्र में अच्छा नहीं रहा। इसलिए वह इस बार टीम में बदलाव चाहती है। इसी कारण फ्रेंचाइजी प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा जैसे दो खिलाड़ियों को रिलीज करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इन दोनों खिलाड़ियों को पिछले आक्शन में 14.20-14.20 करोड़ रुपये की बड़ी रकम देकर खरीदा गया था। इस कदम का मुख्य उद्देश्य नीलामी के लिए अपने पर्स को बढ़ाना है, जिससे टीम के पास बड़े खिलाड़ियों पर दांव लगाने के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध हो सके।अभी सीएसके के पास 2.40 करोड़ रुपये का पर्स बचा हुआ है, जिसमें वार्षिक सैलरी कैप में 5 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी भी शामिल होगी। अगर प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा दोनों को रिलीज किया जाता है, तो टीम के पास अतिरिक्त 28.40 करोड़ रुपये आ जाएंगे। इस तरह, अन्य संभावित बदलावों से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के पास कुल लगभग 35.80 करोड़ रुपये का एक मजबूत पर्स हो सकता है। यह बड़ा पर्स सीएसके को नीलामी में अपनी पसंद के बड़े खिलाड़ियों पर दांव लगाने और अपनी टीम को और भी मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगा।

न्यूज ब्रीफ

घरेलू क्रिकेट से ही होगी हार्दिक की भारतीय टीम में वापसी : शुभमन



आकलैंड। भारतीय टेस्ट और एकदिवसीय कप्तान शुभमन गिल का कहना है कि लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे आलराउंडर हार्दिक पंड्या की राष्ट्रीय टीम में वापसी तभी होगी जब वह घरेलू क्रिकेट में अपनी फिटनेस साबित करेंगे। शुभमन के अनुसार हार्दिक को पहले मुश्ताक अली ट्राफी या विजय हजारे ट्राफी में खेलकर अपनी लय हासिल करनी होगी। पंड्या चोटिल होने के कारण पिछले काफी समय से टीम से बाहर हैं। इसी कारण वह न्यूजीलैंड दौर में भी शामिल नहीं किये गये। शुभमन ने माना है कि हार्दिक जैसे आलराउंडर की टीम को जरुरत है पर कहा कि उनकी वापसी में जल्द बाजी कर जोखिम नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि टीम प्रबंधन विश्व कप के लिए हार्दिक की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कप्तान के अनुसार, हार्दिक एक असाधारण आल-राउंडर है, उनकी जैसी क्षमता दुनिया के बहुत कम खिलाड़ियों के पास है। उन्होंने हार्दिक की गेंदबाजी कौशल की भी सराहना की, यह बताते हुए कि उन्हें एक गेंदबाज के तौर पर खेल के अलग-अलग हिस्सों में, चाहे वह नई गेंद हो या पुरानी, इस्तेमाल किया जा सकता है।साथ ही कहा कि उनकी हार्दिक से कई बार बात हुई है और वह अपनी चोटों को लेकर बदकिस्मत रहे हैं। गिल ने कहा, हार्दिक आईपीएल के बाद से ही नहीं खेले हैं। उम्मीद है, वह जल्द ही वापस आएंगे। वह कुछ घरेलू क्रिकेट खेलेंगे।

टीम में जगह नहीं मिलने से निराश हैं सरफराज

नई दिल्ली। घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद भी राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिलने से



बल्लेबाज सरफराज खान निराश हैं। सरफराज का कहना है उन्हें लगातार मेहनत के बाद भी उसका फल नहीं मिल रहा। जिससे अब उन्हें लगता है कि वह इतनी मेहनत ही क्यों कर रहे हैं। फरवरी 2024 में भारतीय टेस्ट टीम में पदार्पण के बाद सरफराज ने अपना आखिरी टेस्ट अक्टूबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला था। उसके बाद उन्हें बाहर कर दिया गया था ओर तभी से वह वापसी की राह देख रहे हैं। सरफराज ने कहा कि अब वह अधिक सोचते नहीं हैं, लेकिन हर सुबह उठकर उनके मन में यही सवाल आता है, आखिर मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी चाहिए उन्होंने आगे कहा कि सुबह पांच बजे उठने के साथ वही पुरानी दिनचर्या शुरू हो जाती है। सरफराज ने माना है न्यूजीलैंड के खिलाफ 2024 में पुणे और मुंबई में खेले गए पिछले चार टेस्ट पारियों में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, जहां उन्होंने वह 11, 9, 0 और 1 रन बनाए थे। इसी के बाद उन्हें भारतीय टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया। हालांकि, इस मुश्किल दौर में उनके पिता नौशाद खान ही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा बने हुए हैं। सरफराज ने बताया कि जब कभी निराशा उन्हें घेरती है और मेहनत जारी रखने पर सवाल उठता है, तो पिता से ही उन्हें और बेहतर खेलने की प्रेरणा मिलती है।

लंचेनबी चानू: यूथ ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास, वुशु में ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनीं



डकार (सेनेगल)। भारतीय वुशु खिलाड़ी राजकुमारी लंचेनबी चानू ने यहां यूथ ओलंपिक खेलों की महिला चांगक्वान संयुक्त स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वह वुशु में इस प्रतियोगिता का पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। मणिपुर की रहने वाली चानू ने कुल 18.039 अंक हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। मिस्र की सोंडोस सोनबोल ने 18.660 अंक के साथ स्वर्ण पदक जबकि वेनेजुएला की वालेरिया फ्रैनरीस डुडामेल ने 18.199 अंक के साथ रजत पदक जीता। भारतीय खिलाड़ी ने चांगक्वान स्पर्धा में 9.316 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया जबकि गुनशु स्पर्धा में 8.723 अंक के साथ वह तीसरे स्थान पर रहीं। डकार यूथ ओलंपिक में भारत अब तक एक रजत और दो कांस्य पदक जीत चुका है। इससे पहले सोमवार को यूथ खिलाड़ी खुशबू राजकभाई ने रजत पदक जीतकर प्रतियोगिता में अपना अभियान समाप्त किया था। वह यूथ ओलंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय जुडोका बनी थीं। वहीं तैराकी की उभरती खिलाड़ी धिनिधि देसिंघु ने भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए महिला 100 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया था।

एशियन पैरा गेम्स में उपलब्धियों की बरसात : 1538 पदक जीते गए, 27 विश्व रिकार्ड टूटे

नई दिल्ली

जापान के आइची-नागोया में आयोजित 2026 एशियन पैरा गेम्स का समापन कई ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ हुआ। छह दिनों तक चले इस खेल महाकुंभ में कुल 1538 पदक प्रदान किए गए, जबकि खिलाड़ियों ने 27 विश्व रिकार्ड ध्वस्त कर दिए। इसके अलावा प्रतियोगिता के दौरान 81 एशियाई रिकार्ड और 306 एशियन पैरा गेम्स रिकार्ड भी बनाए गए। एशियन पैरा गेम्स के पांचवें संस्करण में 45 देशों की राष्ट्रीय पैरालंपिक समितियों ने हिस्सा लिया। इनमें से 33 देशों ने कम से कम एक पदक अपने नाम किया, जबकि 22 देशों के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की। पदकों के मामले में इस बार पिछले संस्करण के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला।



चीन का दबदबा बरकरार, जापान ने रचा इतिहास

पदक तालिका में चीन ने अपना दबदबा कायम रखते हुए पहला स्थान हासिल किया। चीन ने कुल 435 पदक जीते, जिनमें 207 स्वर्ण, 117 रजत और 111 कांस्य पदक शामिल रहे। मेजबान जापान ने अपने इतिहास का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। जापानी खिलाड़ियों ने 64 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले जापान का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2018 में इंडोनेशिया में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में रहा था, जहां उसने 45 स्वर्ण पदक जीते थे। उज्बेकिस्तान तीसरे स्थान पर रहा, जबकि भारत ने चौथा और दक्षिण कोरिया ने पांचवां स्थान हासिल किया।

27 विश्व रिकार्ड और 306 गेम्स रिकार्ड बने

प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने रिकार्ड प्रदर्शन करते हुए 27 विश्व रिकार्ड तोड़े। यह संख्या पिछले संस्करण की तुलना में सात अधिक रही। विश्व रिकार्ड बनाने में पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ियों का सबसे बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने 11 नए विश्व रिकार्ड अपने नाम किए। इसके अलावा 81 एशियाई रिकार्ड भी बनाए गए, जबकि 306 नए एशियन पैरा गेम्स रिकार्ड दर्ज हुए। ये दोनों आंकड़े 2022 में हांगझोउ में आयोजित पिछले संस्करण के रिकार्ड से अधिक रहे। हांगझोउ में 71 एशियाई रिकार्ड और 279 गेम्स रिकार्ड बने थे।

ताजिकिस्तान और कंबोडिया ने पहली बार जीते पदक

इस बार प्रतियोगिता में कुछ देशों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियां भी देखने को मिलीं। ताजिकिस्तान ने पैरा जूडो में अपना पहला एशियन पैरा गेम्स पदक जीता, जबकि कंबोडिया ने पैरा एथलेटिक्स में पहली बार पदक हासिल कर इतिहास रच दिया।

पदकों से आगे है एशियन पैरा गेम्स की असली विरासत : माजिद राशिद

समापन समारोह को संबोधित करते हुए एशियन पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष माजिद राशिद ने कहा कि इन खेलों की असली सफलता केवल पदकों और रिकार्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका महत्व आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर अवसर तैयार करने में है। उन्होंने कहा, रिकार्ड कायम रहेंगे, पदक संजोकर रखे जाएंगे और यादें हमेशा बनी रहेंगी। लेकिन आइची-नागोया 2026 की असली विरासत इस बात से तय होगी कि हम आगे क्या करते हैं। अधिक खिलाड़ियों को अपनी क्षमता पहचानने का अवसर मिले, अधिक देश अपनी प्रतिभाओं को विकसित करें और दिव्यांगजनों को खेल और समाज में उनका उचित स्थान मिले।

खेलों ने दिया एकता और बदलाव का संदेश एपीसी अध्यक्ष ने खेलों की एकजुट करने वाली ताकत पर जोर देते हुए कहा कि नागोया से सभी देश खेल के जरिए लोगों को जोड़ने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के विश्वास के साथ विदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेलों का आयोजन भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन इससे प्रेरित हुए सपनों और उम्मीदों का सिलसिला जारी रहना चाहिए।

कैसा रहा भारतीय दल का प्रदर्शन

भारत ने एशियन पैरा गेम्स 2026 में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। जापान के आइची-नागोया में आयोजित इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने 30 स्वर्ण, 35 रजत और 49 कांस्य सहित कुल 114 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही भारत ने 2023 में चीन के हांग्झू में बनाए गए अपने पिछले रिकार्ड को पीछे छोड़ दिया। हांग्झू में भारत ने 27 स्वर्ण सहित कुल 108 पदक जीते थे।

पदक तालिका में किस स्थान पर भारत

भारत फिलहाल पदक तालिका में चौथे स्थान पर है, लेकिन कुछ स्पर्धाओं के फाइनल होने के कारण उसकी स्थिति बदल सकती है। भारत का उन स्पर्धाओं में कोई खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले रहा है। अभियान के आखिरी दिन भारत ने नौ स्वर्ण पदक जीते जो इस चरण में उसका एक दिन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ये स्वर्ण पदक तीरंदाजी, निशानेबाजी, बैडमिंटन और एथलेटिक्स में मिले। एथलेटिक्स ने हमेशा की तरह भारत के लिए पदक संख्या में इजाफा किया।

बाबर अपनी बल्लेबाजी लय हासिल करने विदेशी कोच की सेवाएं लें : मोहम्मद यूसुफ



लाहौर

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम को सलाह दी है कि वह घरेलू नहीं बल्कि विदेशी कोच की सेवाएं लें। यूसुफ ने साथ ही कहा कि उन्हें फिलहाल घरेलू क्रिकेट खेलने की जगह पर अपनी बल्लेबाजी की तकनीकी खामियों को दूर करने आस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका जाकर विशेषज्ञ कोचों के साथ अभ्यास करना होगा। इसके बाद ही वह अपनी पुरानी लय हासिल कर पायेंगे। यूसुफ ने कहा कि बिना तकनीक में सुधार किए बिना ही घरेलू क्रिकेट में लगातार संघर्ष करने से बाबर का मनोबल और कम हो जाएगा। इससे उनकी बल्लेबाजी और खराब ही होगी। यूसुफ ने कहा कि हाल में हुई श्रीलंका त्रिकोणीय सीरीज में भी बाबर एक भी मैच में सहज नहीं दिखे। लक्ष्य का पीछा करते हुए बाबर कोई बड़ी पारी नहीं खेल सके। इस प्रदर्शन ने एक बार फिर उनकी फार्म और टीम में भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए।

पूर्व कप्तान ने सुझाव दिया कि बाबर अपना पूरा समय बल्लेबाजी सुधारने में लगाएं और दक्षिण अफ्रीका या आस्ट्रेलिया की किसी अच्छी क्रिकेट अकादमी में विशेषज्ञ कोचों के साथ काम करें। यूसुफ ने कहा कि उन्होंने करीब चार साल पहले भी यही सलाह बाबर को दी थी, लेकिन तब किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उनके मुताबिक, बाबर अभी पाकिस्तान के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक हैं और सही मार्गदर्शन तथा थोड़ी मेहनत से वह अपनी पुरानी लय हासिल कर सकते हैं। बाबर पिछले तीन साल में एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में केवल एक शतक लगा पाये है, जबकि उनके नाम कुल 20 शतक दर्ज हैं। उन्हें पहले ही पाकिस्तान की टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम से बाहर किया जा चुका है और 2027 के एकदिवसीय विश्व कप के लिए टीम में जगह बनाने हेतु उन्हें अपने प्रदर्शन में बड़ा सुधार करना होगा।हालांकि, पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी बाबर की खराब फार्म को अलग-अलग नजरिए से देख रहे हैं।

हाल में पूर्व कप्तान वकार यूनुस ने कहा था कि बाबर के साथ यह दुर्भाग्य रहा कि उन्हें साथी खिलाड़ियों से जरूरी सहयोग नहीं मिला। वहीं, पूर्व आलराउंडर इमाद वसीम ने भी बाबर का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी को मीडिया, आलोचकों और सोशल मीडिया पर इतनी आलोचना और नफरत का सामना करते नहीं देखा।

सुरेश रैना ने CSK से मांगी कोचिंग की जिम्मेदारी:कहा- फ्रेंचाइजी से बात की



चेन्नई। पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने चेन्नई सुपर किंग्स के कोचिंग स्टाफ से जुड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने फ्रेंचाइजी से कोचिंग में जगह देने की मांग भी की है। हालांकि, अब तक उन्हें इस बारे में कोई जवाब नहीं मिला है। रैना ने चेन्नई सुपर किंग्स में पूर्व साथी रहे रविचंद्रन अश्विन के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा- 'मैंने अपनी इच्छा बता दी है और अब फैसला ह्स्च को करना है। मेरे लिए सबसे अहम बात चेन्नई के साथ रहना और टीम को ट्रॉफी जिताने में मदद करना है। रैना ने ह्स्च के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए रैना को उनके चेन्नई सुपर किंग्स प्रदर्शन के कारण 'मिस्टर चेन्नई सुपर किंग्स के नाम से जाना जाता है। संन्यास के बाद वे क्रिकेट एक्सपर्ट और कमेंटेटर के तौर पर काम कर रहे हैं। रैना 2008 के 2021 तक ह्स्च से जुड़े रहे। बीच में जब चेन्नई सुपर किंग्स 2 साल के लिए सस्पेंड थी, तब 2016 और 2017 के सीजन में उन्होंने नई टीम गुजरात लायंस की कप्तानी की थी। रैना चेन्नई सुपर किंग्स के साथ धोनी की कप्तानी में IPL में 4 खिताब और 2 चैंपियंस लीग खिताब जीते। वे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं।

डब्ल्यूटीए 125 टेनिस टूर्नामेंट आयोजित करने की योजना बना रहा टीएनटीए

चेन्नई

तमिलनाडु टेनिस संघ (टीएनटीए) अगले साल से देश में तीन से चार डब्ल्यूटीए 125 टेनिस टूर्नामेंट आयोजित कर सकता है। दिग्गज टेनिस स्टार विजय अमृतराज भी टीएनटीए के इस कदम का समर्थन कर रहे है। उनका कहना है कि चेन्नई ओपन जैसे डब्लूटीए टूर्नामेंट की मेजबानी खोने के बाद किसी न किसी मुकाबले की सख्त जरुरत है। जिससे कि उभरती हुई प्रतिभाओं को कोई मंच मिल सके।

अमृतराज का कहना है कि चेन्नई ओपन को भारत में ही बनाये रखे जाने की जरुरत थी पर डब्ल्यूटीए इसके लिए तैयार नहीं था। इसके पीछे उसने खराब मौसम और फिलीपींस की एलेक्जेंड्रा इला के उभरने को बताया। एलेक्जेंड्रा के विजेता बनने के कारण नियमों के तहत टूर्नामेंट की मेजबानी फिलीपींस को दे दी गयी। अमृताराज ने ये भी माना है कि मौसम ठीक नहीं होने के कारण भारत में चेन्नई ओपन में बेहतर रैंकिंग वाले अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी नहीं आ रहे थे। इससे भी फिलीपींस का पलड़ा भारी पड़ गया।

इला, महिला रैंकिंग में शीर्ष 20 खिलाड़ियों में शामिल हैं और विंबलडन में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद से ही एक स्टार के रुप में उभरी हैं। उनके कारण भी टूर्नामेंट फिलीपींच चला गया। अमृतराज ने कहा कि हम 2027 के लिए फिलहाल डब्ल्यूटीए 250 टूर्नामेंट आयोजित करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं पर डब्ल्यूटीए 125 और 125 प्लस एच श्रेणी के कुछ और टूर्नामेंट आयोजित कराने की दिशा में हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। हम जनवरी-फरवरी 2028 में तीन या चार टूर्नामेंट कराने की उम्मीद कर रहे हैं।

इसका मुख्य लक्ष्य भारतीय खिलाड़ियों, खासकर महिला खिलाड़ियों को



अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खेलने का अवसर दिलाना है। अभी महिला खिलाड़ियों के पास केवल एक ही अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है जो पर्याप्त नहीं है। अमृतराज ने कहा, इससे वैष्णवी, सहजा और अन्य भारतीय लड़कियों को लगातार कई टूर्नामेंट खेलने का मौका मिलेगा। उन्हें सिर्फ एक डब्ल्यूटीए 250 टूर्नामेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।।

अमृतराज का मानना है कि डब्ल्यूटीए 125 टूर्नामेंटों की यह श्रृंखला भारतीय खिलाड़ियों को रैंकिंग अंक जुटाने और पेशेवर टेनिस में आगे बढ़ने का बेहतर अवसर दे सकती है। साथ ही कहा कि अगर आप अच्छा खेलने में सक्षम हैं तो डब्ल्यूटीए 250 टूर्नामेंट में दो मैच जीतने पर निश्चित रूप से ज्यादा अंक मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मुख्य ड्रा में जगह बनानी होती है, जिसके लिए वाइल्ड कार्ड जैसी व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता है। डब्ल्यूटीए 125 टूर्नामेंट में मुख्य ड्रा में जगह बनाना आम तौर पर अधिक आसान होता है।

इंदौर टेबल टेनिस लीग : पावर पैंथर ने 8-3 से दर्ज की जीत, तीन अन्य टीमें भी जीतीं

चैलेंज मैचों में थंडर स्ट्राइकर्स, स्मैश मास्टर्स, ओलिंपिया वारियर्स और विक्ट्री ईगल ने किया पलटवार

इंदौर

द्वितीय इंदौर टेबल टेनिस लीग के शुरुआती मुकाबलों में पावर पैंथर, टेबल टाइटन्स, रायल ब्लेजर और स्पिन एवेंजर्स ने जीत दर्ज की। पावर पैंथर ने थंडर स्ट्राइकर्स को 8-3 से हराया, जबकि अन्य तीन टीमों ने भी अपने मुकाबले जीते। चैलेंज मैचों में चारों मुकाबलों के परिणाम पलट गए। मुख्य मैचों में हारने वाली टीमों ने चैलेंज मैच जीतकर वापसी की। प्रतियोगिता इंदौर जिला टेबल टेनिस संगठन के तत्वावधान में अभय प्रशाल में खेली जा रही है।

पावर पैंथर ने थंडर स्ट्राइकर्स को 8-3 से पराजित किया। विजेता टीम की ओर से मृदुल पुरोहित ने लक्ष्या ओझा, आरवी जैन ने सिद्धिक्षा जैन, प्रशांत-प्रथम ने नीरज-रुद्र, आर्जव पाठक ने पुण्यांश जैन, भाव्यांशी सोनी ने ईवा खान, नक्षत्रराज सिंह ने आर्या गुप्ता, अबीर सोनगरा ने मृनाल ठाकुर, हिया पटेल ने पूजा भार्गव, प्रशांत महंत ने नीरज और प्रथम बाथम ने रुद्र को 2-0 से हराया। चैलेंज मैच में थंडर स्ट्राइकर्स ने पावर पैंथर को 6-5 से पराजित किया।

टेबल टाइटन्स ने स्मैश मास्टर्स को 6-5 से शिकस्त दी। अबु बकर ने मयंक सादेल, नेहल नाहर ने हनु धनोतिया और मनीष-अनुज ने राजेश-चैतन्य को 2-0 से हराया। अर्णव शेगांवकर ने द्युमनी दत्ता को 2-1 से पराजित किया। आर्या जोरे ने नेवेद्य भारतीय, कियान ने रुद्रांश झा और आर्ना उपाध्याय ने भूमिका साहुकार को 2-0 से हराया। मनीष ने चैतन्य करोडे को 2-0 से पराजित किया। चैलेंज मैच में स्मैश मास्टर्स ने टेबल टाइटन्स को 6-4 से हराया।

रायल ब्लेजर ने ओलिंपिया वारियर्स को 6-5 से हराया। वंश चौहान ने अभि जैन, सिद्धि



भदौरिया ने सावी गर्ग, तुषार-कार्तिकेय ने हेमंत-प्रमोद सोनी, सार्थक खरे ने लक्ष्य भदौरिया, दिशा रघुवंशी ने धृति मेहता और आरव कासट ने साकार भार्गव को पराजित किया। अयांश मालू ने शुभ अग्रवाल को 2-1 से तथा राधिका भार्गव ने सुरभि को 2-0 से हराया। प्रमोद सोनी ने तुषार शर्मा और कार्तिकेय कौशिक ने हेमंत रमन को 2-0 से पराजित किया। चैलेंज मैच में ओलिंपिया वारियर्स ने रायल ब्लेजर को 5-4 से हराया।

स्पिन एवेंजर्स ने विक्ट्री ईगल को 6-5 से शिकस्त दी। मृदुल जोशी ने रिदम गदिया को 2-0 से, आकांक्षा ठाकुर ने सानवी सिंघल को 2-1 से, विशाल-रोशन ने कपिल-आराध्या को 2-1 से, मीत मिमरोट ने लक्षित को 2-1 से, आध्या पाराशर ने आरोही मोदी को 2-0 से, आर्यान ठाकुर ने विराट वानखेड़े को 2-0 से, अयान डगरिया ने यदुवीर सिंह सोलंकी को 2-0 से और आराध्या राजपूत ने भाग्यश्री दवे को 2-1 से हराया। विशाल जोशी ने कपिल जैन को 2-0 से तथा रोशन जोशी ने साउद खान को 2-1 से पराजित किया। चैलेंज मैच में विक्ट्री ईगल ने स्पिन एवेंजर्स को 6-1 से हराया।

पहाड़िया के आतिथ्य में हुआ लीग का शुभारंभ - प्रतियोगिता का शुभारंभ इंदौर नगर निगम की महापौर परिषद के सदस्य नंदकिशोर पहाड़िया के मुख्य आतिथ्य तथा मध्यप्रदेश ओलिंपिक संघ के उपाध्यक्ष ओम सानी की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर मध्यप्रदेश टेबल टेनिस संगठन के जयेश आचार्य, प्रमोद सोनी, जिला सचिव नीलेश वेद और गौरव पटेल उपस्थित रहे।



मां लक्ष्मी की पूजा में क्यों चढ़ाते हैं कमल का फूल

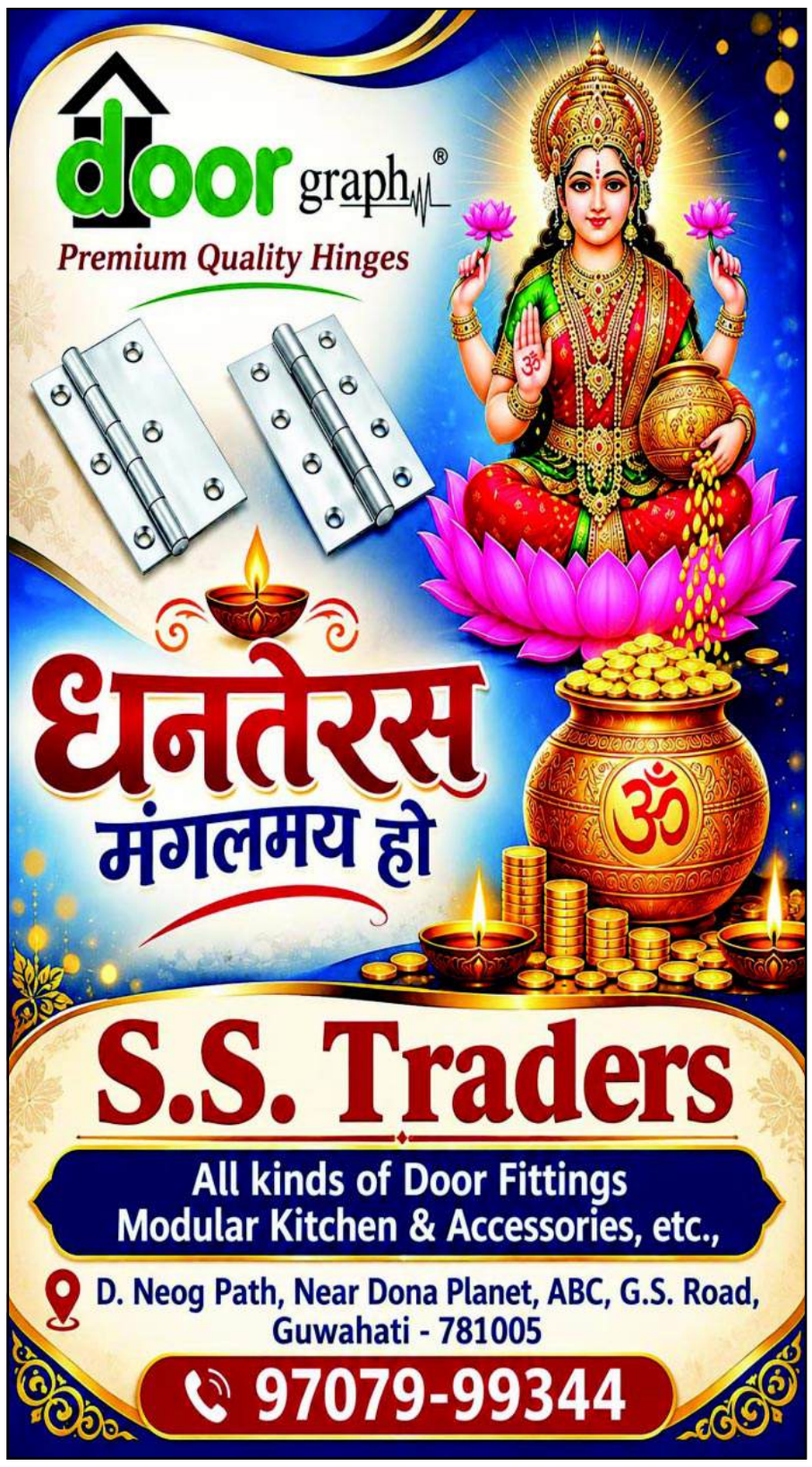


दीवाली पर्व आने में कुछ ही दिन रह गए हैं। पूरे भारत वर्ष में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली का त्योहार रोशनी और उत्साह का है। धनतेरस पर्व से दिवाली फेस्टिवल की शुरुआत हो जाती है। इस साल दीवाली का त्योहार 8 नवंबर 2026, रविवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन शाम को समय माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा जरुर की जाती है। खासकर कुछ लोगों को पता होगा कि लक्ष्मी पूजा की जरुरी बातें। हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें दीवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं लेकिन कुछ खास चीजों को अर्पण करना भूल ही जाते हैं, जो चीज माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। धार्मिक मान्यता है कि *कमल का फूल* लक्ष्मी पूजा में शामिल करने से उनकी कृपा बनीं रहती है। दीवाली पर लक्ष्मी पूजन के दौरान देवी लक्ष्मी को कमल का फूल जरुर अर्पित किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवी लक्ष्मी का अवतार कमल के फूल से ही हुआ था। इसलिए लक्ष्मी पूजा के समय देवी को *अष्टकमल* यानी 8 कमल के फूल चढ़ाए जाते हैं। वहीं, आप चाहे तों मां लक्ष्मी की पूजा में कमल का फूल जरुर अर्पित करें। धार्मिक ग्रंथों में देवी लक्ष्मी का एक नाम *कमला* और *कमलासना* भी है। इसका मतलब कमल पर विराजमान रहने वाली देवी से है। कमल का फूल जिसकी खूबी है कि वो कीचड़ में खिलता है और अपनी संदुरता बनाए रखता है। इस तरह से देवी लक्ष्मी को कमल अर्पित करने वाला मनुष्य भी जीवन में समस्त बुराईयों के बीच अपनी अच्छासे चमक सकते हैं।

कमल के फूल को लेकर श्रीमद्भगवद्गीता में एक श्लोक

श्लोक है- ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः।लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा॥

अर्थात्- जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों में एक समान भावना रखता है, आसक्ति (फल की इच्छा के बगैर) को छोड़कर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देता है, वह पापों से उसी तरह अछूता रहता है, जैसे कमल के पत्ते पानी में रहने बाद भी पानी से नहीं भीगते हैं। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन में माता लक्ष्मी को ताजे, पूरी तरह से खिले हुए कमल के फूल अर्पित करना जरुरी है। इस दौरान उन्हें कोमलता से संभालना चाहिए और भक्ति भावना के साथ देवताओं के चरणों में कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। इस बार दिवाली के पूजन में माता लक्ष्मी को मुरझाए, टूटे या कीट खाए हुए कमल के फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, लापरवाही से नहीं तोड़े और पवित्रता व शुद्ध के साथ देवी लक्ष्मी को अर्पित करें।





प्रकाशक राकेश शर्मा एवं मुद्रक आशीष लाहा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, फाटाशील, 2 नं., कादाबाड़ी मस्जिद के पास, ए.के. देब रोड, गड़चुक, कामरूप मेट्रोपॉलिटन, असम-781035 से मुद्रित एवं **हाउस नं. 26, बिशिनु पथ, बाई 2, रुक्मिणी गांव, कामरूप मेट्रो पॉलिटन, असम-781022 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**